



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 101]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 20, 1997/फाल्गुण 1, 1918

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 20, 1997/PHALGUNA 1, 1918

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड
(शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण)

विनियम 1997

अधिसूचना

मुम्बई, 20 फरवरी, 1997

का०आ० 124(अ):—बोर्ड भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:—(1) ये विनियम भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 1997 कहे जाएंगे।

(2) ये विनियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं:—(1) इन विनियमों में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो:—

(क) "अधिनियम" में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) अभिप्रेत है;

(ख) "अर्जनकर्ता" से कोई व्यक्ति, जो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, या तो स्वयं द्वारा या अर्जनकर्ता के साथ सामान्य मति में कार्य करते हुए, किसी व्यक्ति के साथ लक्ष्य कंपनी में शेयरों या मताधिकारों को अर्जित करना है या अर्जित करने के लिए सहमत होना है, या लक्ष्य कंपनी पर नियंत्रण अर्जित करना है या अर्जित करने के लिए सहमत होना है, अभिप्रेत है;

(ग) "नियंत्रण" के अन्तर्गत निदेशकों के बहुमत की नियुक्ति का अधिकार, या व्यक्ति या सामान्य मति में कार्य करते हुए, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा प्रयोक्तव्य प्रबंध या नीति विनिश्चयों को नियंत्रित करना, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः होंगे, जिनमें उनको जेवरधारिता या प्रबन्ध अधिकारों या शेयरधारकों के कार्यों या मन्दान कार्यों या किसी अन्य रीति में के फलस्वरूप है, सम्मिलित है;

(घ) "अन्वेषण अधिकारी" से विनियम 38 के अर्धीन बोर्ड द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ङ) "सामान्य" मति से कार्य करके हुए व्यक्ति" में समाविष्ट है;—

(1) व्यक्ति, जो शेयरों या मताधिकारों के पर्याप्त अर्जन या लक्ष्य कंपनी पर नियंत्रण बढ़ाने के सामान्य उद्देश्य या प्रयोजन से, करार या बोध (औपचारिक या अनौपचारिक) के अनुसरण में, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः लक्ष्य कंपनी में शेयरों या मताधिकारों या लक्ष्य कंपनी पर नियंत्रण का अर्जन करने हुए या अर्जन करने के लिए सहमत होते हुए सहकार करता है।

(2) इस परिभाषा की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निम्नलिखित व्यक्ति इसी प्रवर्ग में अन्य व्यक्तियों के साथ सामान्य मति से कार्य करते हुए व्यक्ति समझे जाएंगे, जब तक प्रतिकूल स्थापित नहीं हो जाता:

(i) एक कम्पनी, इसकी धारिता कम्पनी, या ऐसी कम्पनी की समनुषंगी या इसी प्रबन्ध के अर्धीन कंपनी या तो व्यक्ति: या प्रत्येक के साथ इकट्ठा;

(ii) इसके किन्हीं निदेशकों के साथ एक कम्पनी या कम्पनी की निधियों के प्रबन्ध में व्यस्त कोई व्यक्ति;

(iii) खंड (2) के उप-खंड (i) में निर्दिष्ट कंपनियों के निदेशक और उनके सहयुक्त;

(iv) पारस्परिक निधि के साथ प्रायोजक या न्यायी या आस्ति प्रबन्ध कंपनी;

(v) उप लेखा (लेखों) के साथ विवेकी संस्थागत विनिधानकर्ता;

(vi) मर्जेंट बैंकर अर्जनकर्ता के रूप में उनके ग्राहक (कों) के साथ;

(vii) संविभाग प्रबन्धक अर्जनकर्ता के रूप में उनके ग्राहक (कों) के साथ;

(viii) जोखिम पूंजी निधियों के साथ प्रायोजक;

(ix) बैंक द्वितीय सलाहकार वाले, अर्जनकर्ता के स्टॉक दलाल, कोई कम्पनी जो एक धारिता कम्पनी है, समनुषंगी या अर्जनकर्ता का संबंधी।

परन्तु यह कि उप-खंड (ix) एक बैंक पर लागू नहीं होगा जिसका अर्जनकर्ता के साथ या किसी कम्पनी के साथ जो एक धारिता कम्पनी या अर्जनकर्ता की एक समनुषंगी है, या अर्जनकर्ता के संबंधी के साथ कमात्र संबंध साजान्य वाणिज्यिक बैंक सेवाएं उपलब्ध करवाने या प्रस्ताव के संबंध में ऐसे कार्यक्रमों जैसे निधियों की प्राप्तता पुष्ट करने, स्वीकारोक्तिपों संबंधी कार्य- और अन्य रजिस्ट्रीकरण कार्य के तौर पर है।

(x) कोई विनिधान कंपनी किसी व्यक्ति के साथ जो निदेशक, विधि प्रबन्धक न्यायी के रूप में हिस्सा रखता हो, या शेयर-धारक के रूप में उस कम्पनी की समादत्त पूंजी का 2%

अन्यून रखता हो या किसी अन्य विनिधान कंपनी के साथ जिसमें ऐसा व्यक्ति या उसका सहयुक्त परचातकथित कंपनी की समादत्त पूंजी का 2% से अन्यून धारण करता हो;

टिप्पणी:—इस खंड के प्रयोजनों के लिए "सहयुक्त" से अभिप्रेत है:—

(क) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 6 के अर्थ के अन्तर्गत उस व्यक्ति का कोई संबंधी; और

(ख) कुटुंब न्यास और हिन्दू अविभक्त कुटुंब।

(च) "प्रस्ताव अवधि" से पहले प्रस्ताव की सार्वजनिक घोषणा की तारीख और उस प्रस्ताव के अंत होने की तारीख के बीच की अवधि अभिप्रेत है;

(छ) "पैनल" से विनियम 4 के प्रयोजन के लिए बोर्ड द्वारा गठित एक पैनल अभिप्रेत है;

(ज) "संप्रवर्तक" से अभिप्रेत है।

(1) (i) एक व्यक्ति या व्यक्ति जो कंपनी के नियंत्रण में है, या

(ii) किसी प्रस्ताव दस्तावेज में संप्रवर्तकों के रूप में नामित एक या अनेक व्यक्ति;

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 6 के अर्थ के भीतर प्रायोजक का एक संबंधी; और

(3) एक नियमित निकाय के मामले में,

(i) उस निकाय की एक समनुषंगी या धारिता कंपनी या

(ii) कोई कंपनी जिसमें "संप्रवर्तक" इक्विटी पूंजी का 10% या अधिक धारण करता है या जो संप्रवर्तक की इक्विटी पूंजी का 10% या अधिक धारण करती है या

(iii) कोई निर्गमित निकाय जिसमें व्यक्तियों का एक समूह या निर्गमित निकायों या इनका समुच्चय जो उस कंपनी में इक्विटी पूंजी का 20% या अधिक धारण करता है "संप्रवर्तक" की इक्विटी पूंजी का भी 20% या अधिक धारण करता है; और

(4) व्यक्ति के मामले में:—

(i) कोई कंपनी जिसमें "संप्रवर्तक" या "संप्रवर्तक" के एक संबंधी या एक पर्स या हिन्दू अविभक्त कुटुंब जिसमें "संप्रवर्तक" या उसका संबंधी भागीदार या महदायिक या इसका एक समुच्चय है, द्वारा शेयर पूंजी का 10% या अधिक धारित है।

(ii) कोई कंपनी जिसमें ऊपर (i) में विनिर्दिष्ट एक कंपनी शेयर पूंजी का 10% या अधिक धारण करती है या

(iii) कोई हिन्दू अविभक्त कुटुंब या फर्म जिसमें संप्रवर्तक और उसके संबंधियों के संकलित शेयर कल के 10% के बराबर या अधिक हैं।

(ख) "लोक वित्तीय संस्था" से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 4क में यथा परिभाषित एक लोक वित्तीय संस्था अभिप्रेत है।

(ज) "सार्वजनिक शेयरधारिता" से अर्जनकर्ता और उसके साथ सामान्य मति से कार्य करते हुए व्यक्तियों से भिन्न व्यक्ति(यों) के पास शेयरधारिता अभिप्रेत है;

(ट) "शेयरों" से एक कंपनी की शेयर पूंजी में मताधिकार युक्त शेयर अभिप्रेत हैं और कोई प्रतिभूति सम्मिलित है जो धारक को मताधिकार युक्त शेयर प्राप्त करने का हकदार बना सकेगी।

(ठ) "रुण औद्योगिक कंपनी" का वही अर्थ होगा जो रुण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 (1986 का 1) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (ग) या इसके किसी कानूनी पुनः अधिनियम में निधन किया गया है।

(ड) "राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था" से राज्य वित्तीय संस्था अधिनियम, 1951 की धारा 3 के अधीन स्थापित एक राज्य वित्त निगम अभिप्रेत है और राज्य में उद्योगों या कृषि क्रिया कलाओं के विकास के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा एक कम्पनी के रूप में स्थापित विकास निगम सम्मिलित है;

(ढ) "स्टॉक एक्सचेंज" से वह स्टॉक एक्सचेंज अभिप्रेत है जिसे प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 4 के अधीन मान्यता प्रदान की गई है;

(ण) "क्षय कंपनी" से वह सूचीबद्ध कंपनी अभिप्रेत है जिसके शेयर या मताधिकार या नियंत्रण प्रत्यक्षतः भा अप्रत्यक्षतः अर्जित किए जाते हैं या अर्जित किए जा रहे हैं;

(2) अन्य सभी पदों के, जब तक इसमें परिभाषित न हों वही अर्थ होंगे जो यथास्थिति अधिनियम या प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956, या कंपनी अधिनियम, 1956 या उसके किसी कानूनी उपांतर या पुनः अधिनियमन के अधीन उनका नियत किए गए हों।

विनियम की प्रयोच्यता :—(1) इस विनियमों के विनियम 10, 11 और 12 की कोई भी बात निम्न पर लागू नहीं होगी :—

(क) एक सार्वजनिक निर्गम को किए गए आवेदन के अनुसरण में आबंटन;

परन्तु यह कि यदि ऐसा एक आबंटन सार्वजनिक निर्गमों में एक पक्ष के आबंटन के अनुसरण में किया जाता है, ऐसे आबंटन की छूट केवल तभी होगी यदि अर्जनकर्ता, जो शेयरों को अर्जित करने के लिए सहमत हो गया हो, का परिचय, अर्जन का प्रयोजन पारिणामिक मताधिकारों में परिवर्तन,

कंपनी की शेयरधारिता क्रम और कंपनी के निदेशक बोर्ड में, यदि कोई हों, और क्या ऐसा आबंटन कंपनी पर नियंत्रण परिवर्तित करने में परिणामित होगा, के बारे में प्राप्तेकृत में पूर्ण प्रकटीकरण किए जाते हैं।

(ख) शेयरधारक द्वारा साधिकार निर्गम के लिए किए गए आवेदन के अनुसरण में आबंटन,

(i) उसकी हकदारी के परिमाण तक; और

(ii) विनियम 11 में विनिर्दिष्ट प्रतिशत तक।

परन्तु यह कि उप-खंड (ii) में उल्लिखित सीमा ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा अर्जन के लिए लागू नहीं होगी जो तत्समय कंपनी के नियंत्रण में है और जिसने सधिकार प्रस्ताव पत्र में प्रकटीकरण किए हों कि वे अपनी हकदारी से अधिक अतिरिक्त शेयरों को अर्जित करने का इरादा रखते हैं यदि निर्गम न्यूनभिस्त हो जाता है।

परन्तु यह और कि प्रतिभूतियों के अर्जन के प्रबन्ध के नियंत्रण में परिवर्तन में परिणामित होने की दशा में यह छूट उपलब्ध नहीं होगी।

(ग) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 81 (1क) के अधीन पारित एक संकल्प के अनुसरण में किया गया अधिमानी आबंटन;

परन्तु यह कि

(i) प्रस्तावित अधिमानी आबंटन की बाबत बोर्ड का संकल्प सभी स्टॉक एक्सचेंजों में, जिन पर कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं सूचना पट्ट पर सूचित किए जाने के लिए है, भेजा जाता है;

(ii) प्रस्तावित आबंटिती (तियों) के वर्ग की पहचान के पूर्ण प्रकटीकरण किए जाते हैं और यदि किसी प्रस्तावित आबंटिती (तियों) को शेयरों की ऐसी संख्या आबंटित की जानी है जो उसकी धारिता को पक्ष निर्गमित पूंजी के 5% या अधिक बढ़ा देगी, तब ऐसे मामलों में, वह कीमत जिस पर आबंटन प्रस्तावित किया जाता है, ऐसे व्यक्ति (यों) की पहचान, ऐसे आबंटन का प्रयोजन और के लिए कारण, कंपनी के निदेशक बोर्ड में पारिणामिक परिवर्तन, यदि कोई हों, और कंपनी के मताधिकार और शेयरधारिता क्रम में और क्या ऐसा आबंटन कंपनी के नियंत्रण में परिवर्तन में परिणामित होगा, के सभी प्रकटीकरण अधिमानी आबंटन के विचार करने के प्रयोजन के लिए बुलाए गए साधारण अधिवेशन की सूचना में किए जाते हैं।

(घ) किसी हामीदारी करार के अनुसरण में हामीदारों को आबंटन;

(ङ) आपस में शायरों के परस्पर अन्तरण :—

(i) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 25) में यथा परिभाषित समूह की परिभाषा के अन्तर्गत आने वाली समूह कंपनियां;

(ii) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 6 के अर्थ के अन्तर्गत संबंधी;

(iii) (क) भारतीय संप्रवर्तक और विदेशी सहयोगी को शेयरधारक है;

(ख) संप्रवर्तक :

परन्तु यह कि उप-खंड (क) तथा (ख) में अन्तरक(कों) और अन्तरलि(तियों) ने व्यष्टितः या सामूहिक रूप से प्रस्तावित अर्जन से पूर्व कम से कम तीन वर्षों की अवधि के लिए लक्ष्य कंपनी में 5% शेयरों से अग्र्यून धारण कर लिया हो;

स्पष्टीकरण :—शेयरधारिता को बढ़ाने के लिए विनियमों की प्रयोज्यता से छूट का उपभोग करने का लाभ या समूह कंपनियों, संबंधियों और संप्रवर्तकों के बीच परस्पर शेयर धारिता के अन्तरण, ऐसी समूह कंपनियों या संबंधियों या संप्रवर्तकों जो विनियम 6, 7 और 8 के अधीन यथा अपेक्षित समूह और वैयक्तिक शेयरधारिता के विवरण दायर करती है, के अधधीन होगा।

(च) कारबार के मामूली क्रम में शेयरों का अर्जन :—

(i) ग्राहकों की ओर से एक स्टॉक एक्सचेंज के एक रजिस्ट्रीकृत स्टॉक दलाल द्वारा;

(ii) बाजार संतुलन के दौरान एक स्टॉक एक्सचेंज के एक रजिस्ट्रीकृत बाजार संतुलनकर्ता द्वारा उन शेयरों की बाबत जिनके लिए वह बाजार संतुलनकर्ता है;

(iii) लोक विस्तीय संस्थाओं द्वारा उनके स्वयं के लेखों में;

(iv) बैंकों और लोक विस्तीय संस्थाओं द्वारा गिरवी-दारों के रूप में;

(घ) उत्तराधिकार या विरासत पर पारयेण के रूप में शेयरों का अर्जन;

(ज) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 617 के अर्थ के अन्तर्गत सरकारी कंपनियों और कानूनी निगमों द्वारा शेयरों का अर्जन;

(झ) राज्य स्तरीय विस्तीय संस्थाओं, जिनके अन्तर्गत उनके समन्वयी हैं से कंपनी के सह-संप्रवर्तक(कों) को ऐसी विस्तीय संस्था और ऐसे सह-संप्रवर्तक(कों) के बीच एक करार के अनुसरण में शेयरों का अन्तरण;

(ञ) (i) रण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 की धारा 18 के अधीन विरचित;

(ii) किसी विधि या विनियम, भारतीय या विदेशी, के अधीन समामेलन या मिलन या विखंडन सहित व्यवस्था या पुनर्गठन की एक स्कीम के अनुसरण में।

(ट) कंपनियों में शेयरों का अर्जन, जिनके शेयर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं;

स्पष्टीकरण :—ऊपर खंड (ट) के अधीन छूट लागू नहीं होगी यदि अर्जन के फलस्वरूप या किसी असूचीबद्ध कंपनी के नियंत्रण के परिवर्तन, चाहे भारत में या विदेश में, अर्जनकर्ता शेयरों या मताधिकारों को अर्जित करता है या एक सूचीबद्ध कंपनी पर नियंत्रण करता है।

(ठ) ऐसे अन्य मामलों में विनियम 4 के अधीन बोर्ड द्वारा अध्याय III की प्रयोज्यता से जो भी छूट दी जाए।

(2) विनियमों के अध्याय III की कोई भी बात सार्व-भौमिक निक्षेपागार रसीदों या अमरीकी निक्षेपागार रसीदों के अर्जन पर लागू नहीं होगी जब तक वे मताधिकार-युक्त शेयरों में संप्रवर्तित नहीं हो जाते हैं।

(3) उप-विनियम (1) के खंड (ग), (ङ), (ज) और (झ) के अधीन अर्जनों की बाबत उन स्टॉक एक्सचेंजों, जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, जनता की जानकारी के लिए, कंपनी की मतदान शेयर पुंजी के 2% से अधिक के अर्जन के मामले में, प्रस्तावित अर्जन की तारीख से कम से कम 4 कार्य-दिवसों पहले प्रस्तावित संव्यवहारों के बारे में सूचित किए जाएंगे।

(4) उप-विनियम 1 के खंड (क), (ख), (ग), (ङ) और (झ) के अधीन अर्जनों की बाबत अर्जनकर्ता, अर्जन की तारीख के 21 दिनों के भीतर, बोर्ड को उन अर्जनों (उसके द्वारा या उसके साथ सामान्य मति से कार्य करते हुए व्यक्तियों द्वारा धारित शेयरों या मताधिकारों, यदि कोई हों, के साथ इकट्ठे किए गए) को बाबत सभी व्यौरों देते हुए समर्थन दस्तावेजों के साथ एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जो ऐसे व्यक्ति को एक कंपनी में मताधिकारों के 10% या अधिक का प्रयोग करने के लिए हकदार बना देगी।

(5) अर्जनकर्ता, उप-विनियम (4) के अधीन निर्दिष्ट रिपोर्ट के साथ, बोर्ड को रु. 10,000 की फीस का संदाय, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के पक्ष में मुम्बई में संदेय या तो बैंकर चैक या मांग ड्राफ्ट द्वारा करेगा।

अधग्रहण पैनल :—4 (1) बोर्ड इस विनियम के प्रयोजनों के लिए अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (5) में वर्णित प्रवर्गों के भीतर से स्वतंत्र व्यक्तियों की बहुसंख्या के एक पैनल का गठन करेगा।

(2) विनियम (3) के उप-विनियम (1) के खंड (1) के अधीन छूट चाहने के लिए, अर्जनकर्ता बोर्ड के पास, प्रस्तावित अर्जन और उन आधारों, जिन पर छूट चाही गई है, के व्यौरों देते हुए, एक आवेदन दाखिल करेगा।

(3) अर्जनकर्ता, उप-विनियम (2) के अधीन निर्दिष्ट आवेदन के साथ, बोर्ड को रु. 25,000/- की फीस का संदाय, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के पक्ष में मुम्बई में संदेय या तो बैंकर चैक या मांग ड्राफ्ट द्वारा करेगा।

(4) बोर्ड उप-विनियम (2) के अधीन आवेदन की प्राप्ति के 5 दिनों के भीतर आवेदन को पैनल को अग्रप्रेषित करेगा।

(5) पैनल आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों के भीतर आवेदन पर सिफारिश बोर्ड को करेगा।

(6) बोर्ड संबद्ध पक्षकारों को युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् और सिफारिशों सहित, यदि कोई हों, सभी सुसंगत तथ्यों पर विचार करने के पश्चात् उप-विनियम (2) के अधीन आवेदन पर एक तर्कसंगत आदेश उसके 30 दिनों के भीतर पारित करेगा।

(7) उप-विनियम 6 के अधीन बोर्ड का आदेश बोर्ड द्वारा प्रकाशित किया जाएगा।

5. कठिनाइयों का निराकरण करने की बोर्ड की शक्ति — इन विनियमों के उपबन्धों के निर्वचन या लागू होने में आने वाली कठिनाइयों का निराकरण करने के लिए, बोर्ड के पास मार्गदर्शन टिप्पणों या परिणतों की मार्गनिर्देशों को जारी करने की शक्ति होगी।

परन्तु यह कि जहां इन विनियमों के किसी उपबन्ध के निर्वचन या लागू होने से संबंधित किसी निदिष्ट मामले में बोर्ड द्वारा कोई निदेश जारी किया जाता है, यह केवल संबद्ध पक्षकारों को एक युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् और निदेश के लिए कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात् ही किया जाएगा।

अध्याय II

शेयरधारिता का प्रकटीकरण और एक सूचीबद्ध कंपनी में नियंत्रण

6. संक्रमणकालीन उपबन्ध :— 1. कोई व्यक्ति, जो किसी कंपनी में पांच प्रतिशत से अधिक शेयर या मताधिकार धारण करता है, इन विनियमों के अधिसूचित होने के दो माह के भीतर उस कंपनी में अपनी कुल शेयरधारिता का प्रकटीकरण, कंपनी को करेगा।

2. प्रत्येक कंपनी जिसके शेयर उप-विनियम (1) में निदिष्ट व्यक्तियों द्वारा धारित हैं, इन विनियमों के अधिसूचित होने की तिथि के तीन महीने के भीतर, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति द्वारा धारित शेयरों की कुल संख्या का प्रकटीकरण उस सभी स्टॉक एक्सचेंजों को करेगी जिन पर कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं।

3. किसी कंपनी पर नियंत्रण रखनेवाला एक प्रवर्तक या कोई व्यक्ति इन विनियमों की अधिसूचना के दो माह के भीतर उस कंपनी में उसके तथा उसके साथ सामान्य मति में कार्य करने वाले व्यक्ति(यों) द्वारा उस कंपनी में धारित शेयरों या मताधिकारों की संख्या और प्रतिशतता का, उस कंपनी को प्रकटीकरण करेगा।

4. प्रत्येक कंपनी जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध हैं, इन विनियमों की अधिसूचना के तीन माह के भीतर, उन सभी स्टॉक एक्सचेंजों को जिन पर कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, प्रवर्तकों और या व्यक्ति(यों) जिनका कंपनी पर नियंत्रण हो, और ऐसे प्रत्येक व्यक्ति द्वारा धारित शेयरों या मताधिकारों की संख्या और प्रतिशतता के बारे में प्रकटीकरण करेगी।

7. एक कंपनी के 5 प्रतिशत और अधिक शेयरों या मताधिकारों का अर्जन :— 1. कोई अर्जनकर्ता, जो शेयरों या मताधिकारों का अर्जन करता है (उसके द्वारा धारित शेयरों या मताधिकारों, यदि कोई हों, के साथ इकट्ठे लिए गए) जो उसे कंपनी में पांच प्रतिशत से अधिक शेयरों या मताधिकारों का हकदार कर देगे, किसी प्रकार से जो भी हो, उस कंपनी में अपनी कुल शेयरधारिता या मताधिकारों का, कंपनी को प्रकटीकरण करेगा।

2. उपविनियम (1) में वर्णित प्रकटीकरण —

- (क) शेयरों के आबंटन की सूचना की प्राप्ति के; या
- (ख) शेयरों या मताधिकारों के अर्जन के, यथास्थिति चार कार्यदिवसों के भीतर किये जायेंगे।

3. प्रत्येक कंपनी, जिसके शेयर उप-विनियम (1) में निदिष्ट रीति में अर्जित किये गये हैं, उप-विनियम (1) के अधीन सूचना की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर ऊपर निदिष्ट ऐसे प्रत्येक व्यक्तियों के द्वारा धारित शेयरों की कुल संख्या का उन सभी स्टॉक एक्सचेंजों को प्रकटीकरण करेगी जिन पर उस कथित कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं।

8. निरंतर प्रकटीकरण :— 1. विनियम (6) में वर्णित व्यक्ति सहित, प्रत्येक व्यक्ति जो किसी कंपनी में दस प्रतिशत से अधिक शेयर या मताधिकार धारण करता है, 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के 21 दिन के भीतर, कंपनी को वार्षिक प्रकटीकरण, 31 मार्च को उसकी धारिताओं के बारे में करेगा।

2. एक प्रवर्तक या कंपनी पर नियंत्रण रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति, 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में 21 दिनों के भीतर, साथ ही लाभांश की घोषणा के प्रयोजनों के लिये कंपनी की अभिलेख तारीख से, उसके द्वारा और उसके साथ सामान्य मति में कार्य करते हुए व्यक्तियों द्वारा, उस कंपनी में धारित शेयरों या मताधिकारों की संख्या और प्रतिशतता का प्रकटीकरण कंपनी को करेगा।

3. प्रत्येक व्यक्ति जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध हैं, 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में 30 दिन के भीतर, साथ ही लाभांश की घोषणा के प्रयोजनों

के लिये कंपनी की अभिलेख तारीख से, उप-विनियम (1) के अधीन निर्दिष्ट व्यक्तियों की धारिताओं और प्रवर्तकों या 31 मार्च को कंपनी पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्तियों की धारिताओं की बाबत भी, परिवर्तनों, यदि कोई हों, का वार्षिक प्रकटीकरण उन सभी स्टॉक एक्सचेंजों को करेगा जिन पर कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं।

4. प्रत्येक कंपनी जिसके शेयर एक स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध हैं, विनियम (6) के उप-विनियम (3), विनियम (7) के उप-विनियम (1) और विनियम (8) के उप-विनियम 2 के अधीन प्राप्त सूचना को अभिलिखित करने के लिये विनिर्दिष्ट रूपविधान में एक रजिस्टर बनाये रखेगा।

9. सूचना मंगाने की शक्ति—स्टॉक एक्सचेंजों और कंपनी बोर्ड को विनियम 6, 7 और 8 के अधीन किये गये प्रकटीकरणों के बारे में सूचना भेजेंगे, जब कभी बोर्ड द्वारा अपेक्षित हों।

अध्याय III

सूचीबद्ध कंपनी में शेयरों या मताधिकारों का पर्याप्त अर्जन और उस पर नियंत्रण का अर्जन

10. किसी कंपनी के शेयरों या मताधिकारों के 10% या अधिक का अर्जन—कोई अर्जनकर्ता ऐसे शेयरों या मताधिकारों का अर्जन नहीं करेगा जो (उसके द्वारा या) उसके साथ सामान्य मति से कार्य करते हुए व्यक्तियों द्वारा धारित शेयरों या मताधिकारों, यदि कोई हों, के साथ इकट्ठे लिये गये) ऐसे अर्जनकर्ता को एक कंपनी में मताधिकारों के दस प्रतिशत या अधिक का प्रयोग करने का हकदार बनाता है, जब तक कि ऐसा अर्जनकर्ता विनियमों के अनुसार ऐसी कंपनी के शेयरों को अर्जित करने के लिये एक सार्वजनिक घोषणा नहीं करता है।

11. धारिताओं का समेकन—(1) कोई अर्जनकर्ता जिसने, उसके साथ सामान्य मति से कार्य करते हुए व्यक्तियों के साथ, विधि के उपबन्धों के अनुसार, एक कंपनी में शेयरों या मताधिकारों का 10% से अन्यून किन्तु 51% से अधिक अर्जित किया हो, या तो स्वयं के द्वारा या उसके साथ सामान्य मति से कार्य करते हुए व्यक्तियों के माध्यम से या के साथ, ऐसे अतिरिक्त शेयरों या मताधिकारों को अर्जित नहीं करेगा जो उसे 12 मास की किसी अवधि में, मताधिकारों का 2% से अधिक का प्रयोग करने के लिये हकदार बनाते हों, जब तक कि ऐसा अर्जनकर्ता विनियमों के अनुसार शेयरों को अर्जित करने की एक सार्वजनिक घोषणा नहीं करता है।

(2) कोई अर्जनकर्ता ऐसे शेयरों या मताधिकारों को अर्जित नहीं करेगा जो (उसके द्वारा या उसके साथ सामान्य मति से कार्य करते हुए व्यक्तियों द्वारा धारित शेयरों या मताधिकारों, यदि कोई हों, के साथ इकट्ठा लिये

गये) ऐसे अर्जनकर्ता को कंपनी में मताधिकारों के 51% से अधिक का प्रयोग करने के लिये हकदार बनाते हैं, जब तक कि ऐसा अर्जनकर्ता विनियमों के अनुसार ऐसी कंपनी का शेयर अर्जित करने के लिये एक सार्वजनिक घोषणा नहीं करता है।

स्पष्टीकरण : विनियम 10 और विनियम 11 के प्रयोजनों के लिये, अर्जन से निम्नलिखित अभिलेख और उसमें सम्मिलित होगा,—

(क) एक सूचीबद्ध कंपनी जिसको विनियम लागू होते हैं, में प्रत्यक्ष अर्जन;

(ख) नियंत्री कंपनियों के अर्जन के आधार पर परोक्ष अर्जन, चाहे सूचीबद्ध हों या असूचीबद्ध, चाहे भारत में हों या विदेश में।

12. किसी कंपनी पर नियंत्रण का अर्जन :—एक कंपनी में शेयरों या मताधिकारों का कोई अर्जन किया गया है या नहीं, का विचार किए बिना, कोई अर्जनकर्ता लक्ष्य कंपनी पर नियंत्रण का अर्जन नहीं करेगा, जब तक कि ऐसा व्यक्ति शेयरों को अर्जित करने के लिये एक सार्वजनिक घोषणा नहीं करता और विनियमों के अनुसार ऐसे शेयरों को अर्जित नहीं करता।

परन्तु यह कि इसकी कोई भी बात नियंत्रण में किसी ऐसे परिवर्तन पर लागू नहीं होगी जो किसी साधारण अधिवेशन में शेयरधारकों द्वारा पारित किमी संकल्प के अनुसरण में होता है।

स्पष्टीकरण :—(i) इस विनियम के प्रयोजनों के लिए जहां लक्ष्य कंपनी पर दो या अधिक व्यक्तियों का नियंत्रण है, वहां न तो ऐसे किसी एक व्यक्ति के ऐसे नियंत्रण की समाप्ति को प्रबंध के नियंत्रण में एक परिवर्तन समझा जायेगा न ही उसके बीच नियंत्रण के स्वरूप और मात्रा में कोई परिवर्तन प्रबंध के नियंत्रण में परिवर्तन का गठन करेगा।

परन्तु तथापि यह कि यदि संयुक्त नियंत्रण का एकल नियंत्रण में अंतरण शेयरों के बाजार मूल्य से कम पर विक्रय के माध्यम से है, तो एक प्रस्ताव-पत्र द्वारा बाहर जाने वाले शेयरधारक के शेयरों के व्ययन की रीति अवधारित करने के लिये लक्ष्य कंपनी के शेयरधारकों की एक बैठक बुलाई जायेगी, या एक विशेष संकल्प द्वारा पारित विनिश्चय के अनुसार नियंत्रण में विद्यमान शेयरधारकों को ब्लाक-अंतरण द्वारा ऐसे मामलों में बाजार-मूल्य विनियम 20 के अनुसार अवधारित किया जायेगा।

(ii) जहां किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को संयुक्त नियंत्रण दिया जाता है, ऐसा नियंत्रण तब तक नियंत्रण में एक परिवर्तन नहीं समझा जायेगा जब तक दिया गया

नियंत्रण तत्समय कंपनी पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति(यों) द्वारा प्रयुक्त नियंत्रण के बराबर या उससे कम न हो।

13. मर्चेट बैंककार की नियुक्ति:—विनियम 10 या विनियम 11 या विनियम 12 में निर्दिष्ट प्रस्ताव की कोई सार्वजनिक घोषणा करने के पहले, अर्जनकर्ता बोर्ड द्वारा प्रदत्त एक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र धारण करने वाला प्रवर्ग I में एक मर्चेट बैंककार नियुक्त करेगा, जो अर्जनकर्ता या लक्ष्य कंपनी का सहयुक्त या का समूह नहीं है।

14. प्रस्ताव की सार्वजनिक घोषणा का समय :—(1) विनियम 10 या विनियम 11 में निर्दिष्ट सार्वजनिक घोषणा मर्चेट बैंककार द्वारा शेयरों या मताधिकारों के अर्जन के लिये एक करार करने या उसमें विनिर्दिष्ट संबंधित प्रतिशतता से अधिक शेयरों या मताधिकारों को अर्जित करने के लिये विनिश्चय करने के 4 कार्य दिवसों के अपश्चात् की जायेगी ;

(2) एक अर्जनकर्ता के प्रतिभूतियों, जिनके अन्तर्गत सार्वभौमिक निक्षेपगार रसीदें या अमरीकी निक्षेपगार रसीदें हैं, के अर्जन की दशा में जो, जब मताधिकारों के साथ इकट्ठी की जाएं, यदि कोई उसके या उसके साथ सामान्य मति से कार्य करते हुए व्यक्तियों द्वारा पहले ही धारित हो, उसे विनियम 10 या विनियम 11 में विनिर्दिष्ट प्रतिशतता से अधिक, मताधिकारों का हकदार बनायेगी, अर्जन करने वाले अर्जनकर्ता के मामले में, उसके द्वारा संपरिवर्तन करने पर ऐसी प्रतिभूतियों के या विकल्प का प्रयोग करने पर यथास्थिति, उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट सार्वजनिक घोषणा, पहले चार कार्य दिवसों के अपश्चात् की जायेगी।

(3) विनियम 12 में निर्दिष्ट सार्वजनिक घोषणा मर्चेट बैंककार द्वारा कियी ऐसे परिवर्तन या परिवर्तनों का, जो अर्जनकर्ता द्वारा लक्ष्य कंपनी पर नियंत्रण के अर्जन में परिणामित होगा (होंगे), विनिश्चय किये जाने के बाद चार कार्य दिवसों के अपश्चात् की जायेगी।

15. प्रस्ताव की सार्वजनिक घोषणा:— (1) विनियम 10 या 11 या 12 के अधीन की जाने वाली सार्वजनिक घोषणा व्यापक परिचालन वाले एक अंग्रेजी राष्ट्रीय दैनिक के सभी संस्करणों, व्यापक परिचालन वाले एक हिंदी राष्ट्रीय दैनिक और व्यापक परिचालन वाले प्रादेशिक भाषा के दैनिक उस स्थान पर जहां लक्ष्य कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है और स्टॉक एक्सचेंज के उस स्थान पर जहां लक्ष्य कंपनी के शेयर सर्वाधिक बार-बार व्यापारित होते हैं, में की जायेगी।

(2) विनियम 10, 11 या 12 के अधीन की जाने वाली सार्वजनिक घोषणा की एक प्रति, मर्चेट बैंककार के माध्यम से इसके जारी होने के कम से कम दो कार्यदिवसों पहले बोर्ड को प्रस्तुत की जायेगी।

(3) बोर्ड को सार्वजनिक घोषणा प्रस्तुत करने के साथ-साथ सार्वजनिक घोषणा उन सभी स्टॉक एक्सचेंजों को भी, जिन पर कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं सूचना बोर्ड पर सूचित किये जाने के लिये, और लक्ष्य कंपनी को कंपनी के निदेशक बोर्ड के समक्ष रखे जाने के लिये इसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में भेजी जायेगी।

(4) इन विनियमों के अधीन प्रस्ताव उस तारीख को किया गया समझा जायेगा जिसको सार्वजनिक घोषणा उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट ममाचारपत्रों में से किसी में भी प्रकट हो।

16. प्रस्ताव की सार्वजनिक घोषणा की विषय-वस्तु:— विनियम 10, 11 या 12 में निर्दिष्ट सार्वजनिक घोषणा में निम्नलिखित विनिर्दिष्टों अंतर्भूत होंगी, अर्थात् :—

- (1) लक्ष्य कंपनी की समादत्त शेयर पूंजी, पूर्णतः समादत्त और अंशतः समादत्त शेयरों की संख्या ;
- (2) विनियम 21 के उप-विनियम (1) में यथा-विनिर्दिष्ट न्यूनतम के अध्वधीन, जनता से अर्जित किये जाने के लिये प्रस्तावित शेयरों की कुल संख्या और प्रतिशतता ;
- (3) प्रत्येक पूर्णतः समादत्त या अंशतः समादत्त शेयर के लिये न्यूनतम प्रस्ताव कीमत ;
- (4) प्रतिफल के संदाय की रीति ;
- (5) अर्जनकर्ता (अर्जनकर्ताओं) की पहचान और यदि अर्जनकर्ता कंपनी या कंपनियाँ हैं, तो संप्रवर्तकों और, या ऐसी कंपनी (कंपनियों) पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्तियों और समूह, यदि कोई हो, जिसका कंपनी (यों) अंग हों, की पहचान ;
- (6) लक्ष्य कंपनी के शेयरों में अर्जनकर्ता की विद्यमान धारिता, यदि कोई हो, जिसमें उसके साथ सामान्य मति से कार्य करते हुए व्यक्तियों की धारितायें सम्मिलित हैं ;
- (7) करार, यदि कोई हो, की प्रमुख बातें, जैसे कि तारीख, विक्रेता का नाम, कीमत जिस पर शेयर अर्जित किये जा रहे हैं, प्रतिफल के संदाय की रीति और उन शेयरों की संख्या और प्रतिशतता जिसकी वास्तव अर्जनकर्ता ने यथास्थिति, शेयरों या प्रतिफल को अर्जित करने के लिये मौद्रिक या से अन्यथा, लक्ष्य कंपनी पर नियंत्रण के अर्जन के लिये करार किया हो ;
- (8) अर्जनकर्ता या उसके साथ सामान्य मति से कार्य करते हुए व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक घोषणा की तारीख के पूर्विक बारह मास की अवधि के दौरान उसके द्वारा लक्ष्य कंपनी के शेयरों के अर्जन, यदि कोई हो, के लिये संदत्त उच्चतम और औसत कीमत ;

- (3) शेयरों के अर्जन और लक्ष्य कंपनी के लिए अर्जनकर्ता की भावी योजनाओं, यदि कोई हो, का उद्देश्य और प्रयोजन, जिसमें प्रकटीकरण सम्मिलित है कि क्या अर्जनकर्ता लक्ष्य कंपनी के कारबार के साधारण अनुक्रम से भिन्न, उत्तरवर्ती दोनों में लक्ष्य कंपनी की किन्हीं आस्तियों के व्ययन का प्रस्ताव करता है या अन्यथा विलग्न करता है।

परन्तु यह कि जहां भावी योजनाएँ उपर्युक्त की जाती हैं, वहां सार्वजनिक घोषणा में यह भी उपर्युक्त होगा कि अर्जनकर्ता किस प्रकार ऐसी भावी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये प्रस्ताव करते हैं।

- (10) विनियम 19 में बर्थावर्णित 'विनिर्दिष्ट तारीख';
- (11) तारीख जिस तक व्यक्तिगत प्रस्ताव पत्र शेयरधारकों में से प्रत्येक को डाक से भेजे जायेंगे;
- (12) प्रस्ताव के खलन और बंद होने की तारीख तथा रीति जिसमें और तारीख जिस तक प्रस्ताव की स्वीकृति या नामंजुरी शेयरधारकों को संसूचित की जायेगी;
- (13) तारीख, जिस तक उन शेयरों के लिये प्रतिफल का संदाय किया जायेगा जिनकी बाबत प्रस्ताव स्वीकार किया गया हो;
- (14) इस आणय का प्रकटीकरण कि प्रस्ताव कार्यान्वित करने के लिये अपेक्षित विनीय संसाधनों के लिये पक्की व्यवस्था पहले ही नियत की गयी है, जिसके अन्तर्गत निधियों के स्रोतों के संबंध में व्यक्ती है कि वे देशी जैसे बैंकों, विनीय संस्थाओं या अन्यथा से हैं, या विदेशी जैसे अनिवार्य भारतीयों से या से अन्यथा;
- (15) व्यक्तियों द्वारा प्रस्ताव की स्वीकृति के लिये उपबंध जो शेयरों के स्वामी हैं परन्तु ऐसे शेयरों के रजिस्ट्रीकृत धारक नहीं हैं;
- (16) कानूनी अनुमोदन, यदि कोई हो, जिन्हें कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1), एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार, अधिनियम, 1969 (1969 का 54), विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46) और/या किन्हीं अन्य प्रयोज्य विधियों के अधीन शेयरों का अर्जन करने के प्रयोजन के लिये अभिवृत्त किया जाना अपेक्षित है;
- (17) बैंकों या विनीय संस्थाओं के अपेक्षित अनुमोदन, यदि कोई हो;

- (18) क्या प्रस्ताव शेयरधारकों के स्वीकारोक्तिओं के न्यूनतम स्तर के अधीन है, और

- (19) ऐसी अन्य जानकारी जो प्रस्ताव के विषय में सूचित विनिश्चय करने के लिये शेयरधारकों के लिये आवश्यक हो।

17. बोशर, विज्ञापन सामग्री आदि :—शेयरों के अर्जन के संबंध में जारी प्रस्ताव की सार्वजनिक घोषणा या किसी अन्य विज्ञापन, परिपत्र, बोशर, प्रचार सामग्री या प्रस्ताव पत्र में कोई भ्रामक जानकारी अंतर्विष्ट नहीं होगी।

18. बोर्ड का प्रस्ताव पत्र प्रस्तुत करना :—(1) यथास्थिति विनियम 10, 11 या 12 के अधीन की गयी सार्वजनिक घोषणा की तारीख से चौदह दिनों के भीतर, अर्जनकर्ता, इसके सर्वोच्च बैंककार के माध्यम से, बोर्ड में, द्वारा यथा विनिर्दिष्ट प्रकटीकरणों से युक्त, प्रस्ताव पत्र का प्रारूप दाखिल करेगा।

(2) प्रस्ताव-पत्र, उप-विनियम (1) के अधीन बोर्ड को इसके प्रस्तुतीकरण से 21 दिनों के पूर्वतम शेयरधारकों को प्रेषित नहीं किया जायेगा।

परन्तु यह कि यदि, प्रस्ताव पत्र के प्रस्तुतीकरण की तारीख से 21 दिनों के भीतर, बोर्ड प्रस्ताव पत्र में, परिवर्तनों, यदि कोई हों, के विनिर्दिष्ट करता है, (ऐसा करने की किसी बाध्यता के अधीन रहते हुए बिना), सर्वोच्च बैंककार और अर्जनकर्ता शेयरधारकों को प्रस्ताव पत्र प्रेषित करने से पूर्व ऐसे परिवर्तन करेंगे।

(3) अर्जनकर्ता, उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट प्रस्ताव-पत्र के प्रारूप के साथ, बोर्ड को, मुंबई में संदेय, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के पक्ष में या तो बैंकर बैंक या मांगदेय ड्राफ्ट द्वारा 50,000 रु. की फीस का संदाय करेगा।

19. विनिर्दिष्ट तारीख :—सार्वजनिक घोषणा में एक तारीख विनिर्दिष्ट होगी, जो शेयरधारकों जिनको प्रस्ताव-पत्र भेजा जाना चाहिये के नाम अवधारित करने के प्रयोजन के लिये "विनिर्दिष्ट तारीख" होगी।

परन्तु यह कि ऐसी विनिर्दिष्ट तारीख सार्वजनिक घोषणा की तारीख से तीसरे दिन के अपश्चात् होगी।

20. न्यूनतम प्रस्ताव कीमत :—(1) विनियम 10, 11 या 12 के अधीन शेयरों को अर्जित करने के लिये प्रस्ताव न्यूनतम प्रस्ताव कीमत पर दिया जायेगा जो निम्नानुसार संदेय होगा—

(क) नकद रूप में; या

(ख) विनियम और, या अर्जनकर्ता कंपनी के शेयरों के अंतरण, द्वारा, यदि शेयरों को अर्जित करने का इच्छुक व्यक्ति एक सूचीबद्ध निगमित निकाय है; या

(ग) साख निर्दिष्ट एनीमी से न्यूनतम "ए" ग्रेड वाले प्रतिभूत लिखतों के विनिमय और/या संतरण द्वारा;

(घ) खंड (क), (ख) या (ग) का समुच्चय;

परन्तु यह कि जहां शेयरधारकों के किसी वर्ग को उनके शेयरों को अर्जित करने के लिये किसी करार के अधीन या खुले बाजार में किसी अर्जन के अनुसरण में या सार्वजनिक घोषणा की तारीख से पूर्ववर्ती 12 मास के दौरान किसी अन्य रीति में संदाय नकद रूप में किया गया हो, वहां प्रस्ताव दस्तावेज उपबंध करेगा कि शेयरधारकों के पास या तो नकद रूप में या शेयरों के विनिमय या ऊपर निर्दिष्ट अन्य प्रतिभूत लिखतों द्वारा संदाय स्वीकार करने का विकल्प है।

(2) उप विनियम (1) के प्रयोजनों के लिये, न्यूनतम प्रस्ताव कीमत निम्नलिखित का उच्चतम होगी—

(क) विनियम 14 के उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट करार के अधीन बातचीत से तय की गई कीमत;

(ख) अर्जनकर्ता या उसके साथ सामान्य मति से कार्य करते हुए व्यक्तियों द्वारा किन्हीं अर्जनों के लिये संदत्त उच्चतम कीमत, जिसमें सार्वजनिक घोषणा की तारीख से पूर्व 26 सप्ताह की अवधि के दौरान सार्वजनिक या साधिकार निर्गम में आबंटन के रूप में, यदि कोई हो, सम्मिलित है;

(ग) अर्जनकर्ता द्वारा प्रस्ताव के बंद होने की तारीख तक बारह मास की अवधि के दौरान किसी भी समय, उमे या उसके साथ सामान्य मति से कार्य करते हुए व्यक्तियों को किये गये किसी अधिमानी आबंटन के अधीन संदत्त कीमत;

(घ) स्टॉक एक्सचेंज, जहां कंपनी के शेयर सार्वजनिक घोषणा की तारीख के पूर्ववर्ती 26 सप्ताह के दौरान बहुधा बार-बार व्यापारित होते हैं, में यथा उत्कृष्ट लक्ष्य कंपनी के शेयरों की बंद कीमतों के साप्ताहिक उच्च और न्यून का औसत हो।

(3) जहां लक्ष्य कंपनी के शेयर बार-बार व्यापारित नहीं होते हैं, वहां प्रस्ताव कीमत निर्गमकर्ता और सर्वोच्च बैंकर द्वारा निम्नलिखित बातों पर विचार करके अधिधारित की जायेगी;

(क) विनियम 14 के उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट करार के अधीन बातचीत से तय की गई कीमत;

(ख) अर्जनकर्ता या उसके साथ सामान्य मति से कार्य करते हुए व्यक्तियों द्वारा अर्जनों के लिये

संदत्त उच्चतम कीमत, जिसमें सार्वजनिक घोषणा की तारीख से पूर्व छब्बीस सप्ताह की अवधि के दौरान सार्वजनिक या साधिकार निर्गम में आबंटन के रूप में, यदि कोई हो, सम्मिलित है;

(ग) अर्जनकर्ता द्वारा प्रस्ताव के बंद होने की तारीख तक बारह मास की अवधि के दौरान किसी भी समय, उमे या उसके साथ सामान्य मति से कार्य करते हुए व्यक्तियों को किये गये किसी अधिमानी आबंटन के अधीन संदत्त कीमत; और

(घ) अन्य परिभाषा जिनमें शुद्ध मूल्य पर प्रत्यागम, लक्ष्य कंपनी के शेयरों का वही मूल्य, प्रति शेयर उपार्जन, उद्योग औसत के मुकाबले में कीमत उपार्जन गुणज सम्मिलित है।

स्पष्टीकरण :— (i) इस खंड के प्रयोजन के लिये, शेयरों को बार-बार व्यापारित न हुआ समझा जायेगा यदि भारत में स्टॉक एक्सचेंज में उस शेयर में उस मास के पूर्व जिसमें सार्वजनिक घोषणा की जाती है पूर्विक 6 पूर्ववर्ती कैलेंडर मास के दौरान वार्षिक व्यापार आवर्त सूचीबद्ध शेयरों के दो प्रतिशत (शेयरों की संख्या द्वारा) से कम है। इस प्रयोजन के लिये, कथित छह मास के दौरान सूचीबद्ध शेयरों की भारत औसत संख्या ली जाये।

(ii) उन शेयरों के मामले में जो सार्वजनिक घोषणा के पूर्ववर्ती छह मास के भीतर सूचीबद्ध किये गये हैं, व्यापार आवर्त की दिनों जिनके लिये शेयर सूचीबद्ध किया गया हो की वास्तविक संख्या के संदर्भ में वार्षिक किया जा सकेगा।

(4) उपर्युक्त उप-विनियम (1), (2) और (3) के उपबंधों के होते हुए भी, जहां अर्जनकर्ता ने सार्वजनिक घोषणा की तारीख के पश्चात् खुले बाजार में बातचीत से तय करने के माध्यम से, या अन्यथा प्रस्ताव पत्र में कथित न्यूनतम प्रस्ताव कीमत से उच्चतम कीमत पर शेयरों को अर्जित किया हो, तो ऐसी अर्जन की न्यूनतम संदत्त उच्चतम कीमत प्रस्ताव के अधीन प्रस्तावित स्वीकारोक्तियों के लिए संदेय होगी।

(5) उस मामले में जहां प्रस्तावित प्रस्ताव के बंद होने में अर्जनकर्ता कंपनी के बोर्ड तथा अधिधारित प्रस्तावित किये जात हैं, ऐसे शेयरों का प्रतिभूत लिखतों का प्रयोग

उपयुक्त उप विनियम 2 और 3 में यथा वर्णित उरी शीत में, अवधारित प्रयोज्य सीमा तक किया जायेगा, जो एक स्वतंत्र प्रवर्ग 1 के मर्चेट बैंककार (प्रस्ताव के प्रबंधकों ने भिन्न) या दस वर्षों में प्रतिष्ठित एक स्वतंत्र मन्दी लेखा-कार द्वारा सम्यक् रूप में समाहित किया जाए।

(6) प्रस्ताव पत्र में औचित्य जिस पर कीमत अवधारित की गई हो अंतर्विष्ट होगा।

स्पष्टीकरण:—(1) उप विनियम 2 के खंड (ख) के अधीन उच्चतम कीमत या खंड (घ) के अधीन औसत कीमत को कथित अवधि के दौरान अधिकार-सहित या बोनस-सहित आधार पर कोटेशनों, यदि कोई हो, के लिए समा-योजित किया जाए।

(2) जहां प्रस्ताव की सार्वजनिक घोषणा सार्वजनिक निर्धम या अधिमानी आक्टन में पक्के आक्टन के रूप में अर्जन के अनुसरण में है, वहां उप-विनियम 2 के खंड (घ) के अधीन औसत कीमत की गणना बोध-संकल्प जिसने पक्का, अधिमानी आक्टन प्राधिकृत किया है की तारीख से पूर्ववर्ती 26 सप्ताह की अवधि के मंदर्भ में की जायेगी।

(3) जहां शेयरधारकों को या तो नकद रूप में या प्रतिभूति के विनियम के रूप में भुगतान स्वीकार करने के विकल्प की व्यवस्था की गई है तक विनियम 20 के उपबंधों के अध्याधीन, नकद प्रस्ताव के लिए कीमत-निर्धारण उस शेयर विनियम प्रस्ताव के या प्रतिभूत लिखतों के साथ विनियम के लिए प्रस्ताव से भिन्न हो सकती है; परंतु यह कि प्रस्ताव दस्तावेज में प्रकटीकरण ऐसे अंतर्गम्य कीमत-निर्धारण के लिए उपयुक्त औचित्य से युक्त है।

(4) जहां प्रस्ताव स्वीकारोक्तियों के न्यूनतम स्तर के अध्याधीन है, वहां अर्जनकर्ता, विनियम 20 के उपबंध के अध्याधीन, 20% की न्यूनतम स्वीकृति के लिए एक निम्न-तर कीमत उपदर्शन कर सकेगा, प्रस्ताव पूर्ण स्वीकृति प्राप्त नहीं होना चाहिए।

21. अर्जित किये जाने वाले शेयरों की न्यूनतम संख्या:—(1) लक्ष्य कंपनी के शेयरधारकों को सार्वजनिक प्रस्ताव उनसे कंपनी की मतयुक्त पूंजी का न्यूनतम कुल 20% अर्जित करने के लिए किया जायेगा।

परंतु यह कि जहां विनियम 11 के उप-विनियम (2) के अनुसरण में खुला प्रस्ताव किया जाता है, वहां सार्व-जनिक प्रस्ताव कंपनी की मतयुक्त पूंजी की ऐसी प्रति-शतता के लिए किया जाएगा जो अर्जनकर्ता द्वारा विनिश्चित किया जाए।

(2) जहां प्रस्ताव विनियम 16 के खंड (xviii) में यथा उपबंधित शेयरधारकों से स्वीकारोक्तियों के न्यूनतम स्तर पर मशरूफ है, वहां इस विनियम के उप-विनियम (1) के उपबंध प्रयोज्य नहीं होंगे, यदि अर्जनकर्ता ने निम्न

रखने में सार्वजनिक प्रस्ताव के प्रधीन मध्ये प्रतिकूल की 50% की राशि तकद रूप में जमा कर दी हो।

(3) यदि सार्वजनिक प्रस्ताव सार्वजनिक शेयरधारिता में कंपनी की मतयुक्त पूंजी के 10% या कम की कमी करते हुए परिणामित होता है, या यदि सार्वजनिक प्रस्ताव किसी ऐसी कंपनी के बारे में है जिसकी सार्वजनिक शेयरधारिता कंपनी की मतयुक्त पूंजी के 10% से कम की हो, तो अर्जन-कर्ता या तो —

(क) सार्वजनिक प्रस्ताव के बंद होने की तारीख से 3 मास की अवधि के भीतर, शेयरधारकों के पास रखे जोष बकाया शेयरों को उनी प्रस्ताव कीमत पर खरीदने के लिए प्रस्ताव करेगा, जो लक्ष्य कंपनी के असूचीबद्ध करने में परिणामित हो सकेगी; या

(ख) विक्रय के लिए एक प्रस्ताव के माध्यम से या जनता को पूंजी के एक नये निर्गम द्वारा, जो सार्वजनिक प्रस्ताव के बंद होने की तारीख से 6 मास की अवधि के भीतर खुलेगा, शेयरों की ऐसी संख्या का विनिवेश करने का वचन देगा ताकि सूचीबद्ध करने की अपेक्षा पूर्ण हो सके।

(4) प्रस्ताव पत्र में उप-विनियम (3) के अधीन अर्जनकर्ता को उपलब्ध विकल्प का स्पष्ट रूप से कथन होगा।

(5) उप विनियम (1), (2) और (3) में निर्दिष्ट प्रतिशतता की संगणना के प्रयोजन के लिए सार्वजनिक प्रस्ताव के बंद होने के पश्चात् 30 दिनों की समाप्ति पर मताधिकारों की गणना की जायेगी।

(6) जहां शेयरधारकों द्वारा विक्रय के लिए प्रस्तावित शेयरों की संख्या प्रस्ताव करने वाले व्यक्ति द्वारा अर्जित किये जाने के लिए तय शेयरों की संख्या से अधिक है, वहां ऐसा व्यक्ति, पब्लिक बैंककार के परामर्श से, शेयरधारकों से प्राप्त प्रस्तावों को आनुपातिक आधार पर यह सुनिश्चित करते हुए स्वीकार करेगा कि स्वीकृति के आधार का विनिश्चय श्रृज् और साम्य पूर्ण नीति में किया जाता है और अविपणन-योग्य लॉट के रूप में परिणामित नहीं होता है।

परंतु यह कि किसी शेयरधारक से शेयरों का अर्जन न्यूनतम विपणनयोग्य लॉट या संपूर्ण धारिता यदि यह विपणनयोग्य लॉट से कम नहीं होगा।

22. अर्जनकर्ता की सामान्य बाध्यताएं:—(1) लक्ष्य कंपनी के शेयरों को अर्जित करने के लिए प्रस्ताव की सार्वजनिक घोषणा केवल तभी की जाएगी जब अर्जनकर्ता प्रस्ताव कार्यान्वयन करने में समर्थ है।

(2) प्रस्ताव की सार्वजनिक घोषणा के 14 दिनों के भीतर, अर्जनकर्ता लक्ष्य कंपनी को प्रस्ताव पत्र के प्रारूप की एक प्रति इसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते पर, निर्देशक

बोर्ड के समक्ष रखे जाने के लिए, और सभी स्टॉक एक्सचेंजों जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं को प्रेषित करेगा।

(3) अर्जनकर्ता सुनिश्चित करेगा कि प्रस्ताव पत्र लक्ष्य कंपनी के उन सभी शेयरधारकों (यदिवांसी भारतीयों सहित) को भेजे जाने हैं, जिनका नाम सार्वजनिक घोषणा में उल्लिखित विनिर्दिष्ट तारीख को कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में दर्जित हैं, ताकि सार्वजनिक घोषणा की तारीख से 45 दिनों के भीतर उन तक पहुंच जाए।

परंतु यह कि जहां सार्वजनिक घोषणा शेयरों को अर्जित करने के लिए या लक्ष्य कंपनी पर नियंत्रण करने के करार के अनुसरण से की जाती है, वहां प्रस्ताव पत्र करार के पक्षकारों से भिन्न शेयरधारकों को भेजा जाएगा।

स्पष्टीकरण :—(i) प्रस्ताव पत्र की एक प्रति सार्वभौमिक निक्षेपागार रसीदों या अमरीकी निक्षेपागार रसीदों के अभि-रक्षकों को ऐसे व्यक्तियों को खले प्रस्ताव में भाग लेने के लिए समर्थ बनाने के लिए, यदि वे ऐसा करने के हकदार हैं को भी भेजी जाएगी।

(ii) प्रस्ताव पत्र की एक प्रति वारंट धारकों या संपरिवर्तनीय डिबेंचर धारकों को भी भेजी जाएगी जहां विकल्प के प्रयोग की अवधि या संपरिवर्तन, प्रस्ताव अवधि के भीतर, आता है।

(4) प्रस्ताव खुलने की तारीख सार्वजनिक घोषणा की तारीख से सातवें दिन के अपनचात् होगी।

(5) शेयरधारकों से शेयरों को अर्जित करने के लिए प्रस्ताव 30 दिनों की अवधि के लिए खुला रहेगा।

(6) अर्जनकर्ता के एक कंपनी होने की दशा में, प्रस्ताव के संबंध में शेयरधारकों को जारी प्रस्ताव की सार्व-जनिक घोषणा, ब्रोशर, परिपत्र, प्रस्ताव पत्र या कोई अन्य विज्ञापन या प्रचार सामग्री में अवश्य कथन करना चाहिए कि निदेशक ऐसे दस्तावेजों में अंतर्विष्ट जानकारी के लिए जिम्मेदारी प्रतिगृहीत करते हैं।

परंतु यह कि निदेशकों में से कोई ऐसे दस्तावेज में जानकारी के लिए जिम्मेदारी से स्वयं को छूट देने की वांछा करता है, ऐसा निदेशक इस आशय का कथन, ऐसे कथन के लिए उसके कारणों के साथ, जारी करेगा।

(7) प्रस्ताव अवधि के दौरान, अर्जनकर्ता या उसके साथ सामान्य गति में कार्य करते हुए व्यक्ति लक्ष्य कंपनी के निदेशक बोर्ड में नियुक्त किए जाने के लिए हकदार नहीं होंगे।

(8) जहां प्रस्ताव स्वीकृतियों के न्यूनतम स्तर पर सशर्त किया जाता है, वहां अर्जनकर्ता या उसके साथ सामान्य गति में कार्य करता हुआ कोई व्यक्ति :—

(i) प्रस्ताव स्वीकृतियों के न्यूनतम स्तर की अनुक्रिया में प्राप्त हुआ या नहीं का विचार किए बिना, विनियम 21 के उप-विनियम (1) में विनिर्दिष्ट

न्यूनतम प्रतिशतता की सीमा तक जनता से शेयरों को अर्जित करेगा ;

परंतु यह कि इस खंड के उपबंध प्रयोज्य नहीं होंगे यदि अर्जनकर्ता ने निलम्ब खाने में सार्वजनिक प्रस्ताव के अधीन संदेय प्रतिफल का 50% नकद रूप में जमा कर दिया हो।

(ii) प्रस्ताव अवधि के दौरान, लक्ष्य कंपनी में किन्हीं शेयरों को अर्जित नहीं करेगा, सिवाय लक्ष्य कंपनी के शेयरों के नए निर्गम के रूप में, जैसा विनियम 3 के अधीन उपबंधित है;

(iii) विनियमों के अधीन बाध्यताओं को पूरा न करने के लिए, संपूर्ण निलम्ब खाने के समग्रहरण की शर्तों के लिए, दायी होगा ;

(9) यदि अर्जनकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों में से कोई या उसमें हित रखने वाला पहले से ही लक्ष्य कंपनी के बोर्ड में एक निदेशक है या भागधारी (अंत-रंग व्यापार) विनियम, 1992 के अर्थ के अंतर्गत “अंतर्गंग” है, तो यह स्वयं को अलग रखेगा और प्रस्ताव से संबद्ध या “संपृक्त” किसी मामले(लों) जिसके अंतर्गत प्रस्ताव की ओर कोई प्रारंभिक कदम है, में भाग नहीं लेगा।

(10) प्रस्ताव की सार्वजनिक घोषणा के जारी करने की तारीख को या के पहले, अर्जनकर्ता विनियम 28 के अधीन यथा उपबंधित एक निम्ब खाता सृजित करेगा।

(11) अर्जनकर्ता सुनिश्चित करेगा कि सार्वजनिक प्रस्ताव के अधीन बाध्यताएं पूरी करने के लिए पक्की वित्तीय व्यवस्थाएं की गई हों और प्रस्ताव की सार्वजनिक घोषणा में इस संबंध में उपयुक्त प्रकटीकरण किए जाएंगे।

(12) अर्जनकर्ता, प्रस्ताव के बंद होने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर, उन शेयरधारकों को जिन्होंने प्रस्ताव स्वीकार किया है और इस प्रयोजन के लिए विनियम 29 के अधीन यथा उपबंधित एक विशेष खाता खोला है प्रति-फल के संदाय सहित प्रस्ताव से संबंधित सभी प्रक्रियाएं पूरी करेगा।

परंतु यह कि जहां अर्जनकर्ता उन शेयरधारकों को संदाय करने में असमर्थ है जिन्होंने अपेक्षित कानूनी अनुमोदनों की अप्राप्ति के कारण कथित 30 दिनों की अवधि के पहले प्रस्ताव स्वीकार किया है, वहां बोर्ड, यदि बोर्ड का समाधान हो जाता है कि अपेक्षित कानूनी अनुमोदनों की अप्राप्ति अर्जनकर्ता के जानबूझकर किए गए, किसी व्यक्तिक्रम या उपेक्षा के या ऐसे अनुमोदनों के लिए आवेदनों के तत्पश्चात्पूरण अनुमोदन में अर्जनकर्ता की अपफलता के कारण नहीं है, इस प्रयोजन के लिए समय में विस्तार दे सकेगा, जो अर्जनकर्ता के शेयरधारकों को 30 दिनों से अधिक विनिबंध के लिए व्याज का संदाय करने के लिए सहमति देने के अध्वधीन होगा, जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए।

(13) जहाँ अर्जनकर्ता अपनी ओर से जानबूझकर कि, ग, व्यतिक्रम या उपेक्षा या अक्रियता या कार्यवाई न करने के कारण अपेक्षित कानूनी अनुमोदनों को समय पर अभिप्राप्त करने में असफल रहता है, वहाँ अर्जनकर्ता के विनियमों में यथा उपबंधित शास्ति के लिए धायी होने के अलावा, निलम्ब खाते में पूर्ण राशि समपहृत किए जाने का दायी होगा और विनियम 28 के उप-विनियम 12 के खंड (ग) में उपबंधित रीति में निपटान किया जाएगा।

(14) विनियमों के निबंधनों के अनुसार प्रस्ताव के प्रत्याहरण की दशा में, अर्जनकर्ता लक्ष्य कंपनी के शेयरों के अर्जन के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्ताव के प्रत्याहरण की सार्वजनिक घोषणा की तारीख से छह मास की अवधि के लिए नहीं करेगा।

(15) विनियमों के अध्याय III या अध्याय IV के अधीन बाध्यताओं के पूरा न करने की दशा में, अर्जनकर्ता किसी सूचीबद्ध कंपनी के शेयरों के अर्जन के लिए कोई प्रस्ताव, प्रस्ताव के बद होने की तारीख से बारह मास की अवधि के लिए नहीं करेगा।

(16) यदि अर्जनकर्ता, करार के अनुसरण में, उन शेयरों को अर्जित करता है जो उसकी विद्यमान शेयरधारिता, यदि कोई हो, के साथ मिलकर, उसकी शेयरधारिता 10% से अधिक बढ़ा देता है, तो शेयरों के विक्रय के लिए ऐसे करार में इस आशय का एक खंड अंतर्विष्ट होगा कि इस विनियम के किन्हीं उपबंधों के अनुपालन की स्थिति में, ऐसे विक्रय के लिए करार पर विक्रेता या अर्जनकर्ता द्वारा कार्यवाई नहीं की जाएगी।

(17) जहाँ अर्जनकर्ता या उसके साथ सामान्य मति से कार्य करते हुए व्यक्तियों ने सार्वजनिक घोषणा की तारीख के पश्चात् किन्हीं शेयरों को अर्जित किया हो, वह ऐसे अर्जन के 24 घंटों के भीतर स्टॉक एक्सचेंजों को जिन पर लक्ष्य कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं और मर्जेंट बैंकर को, ऐसे शेयरों की संख्या, प्रति-शतता, कीमत और अर्जन की रीति का प्रकटीकरण करेगा।

(18) जहाँ अर्जनकर्ता ने सार्वजनिक घोषणा और या प्रस्ताव पत्र में लक्ष्य कंपनी के कारबार के साधारण अनु-क्रम के अलावा लक्ष्य कंपनी की किन्हीं आस्तियों के व्ययन या अन्यथा विल्लंगम के अपने आशय का कथन न किया हो वहाँ अर्जनकर्ता को, जहाँ उसने लक्ष्य कंपनी पर नियंत्रण अर्जित किया हो, सार्वजनिक प्रस्ताव के बद होने की तारीख से 2 वर्षों की अवधि के लिए लक्ष्य कंपनी की आस्तियों का व्ययन करने या अन्यथा विल्लंगम करने से विवर्जित किया जाएगा।

23. लक्ष्य कंपनी के निदेशक बोर्ड की सामान्य वाध्यताएं:—

(1) प्रस्ताव की सार्वजनिक घोषणा की तारीख के पश्चात् जब तक कि शेयरधारकों के साधारण निकाय का अनुमोदन अभिप्राप्त नहीं होता है, प्रस्ताव अवधि के दौरान लक्ष्य कंपनी का निदेशक बोर्ड;—

(क) कंपनी या इसकी समनुपगियों की, आस्तियों का विक्रय, अन्तरण, विल्लंगम या अन्यथा व्ययन या विक्रय, अन्तरण या व्ययन या विल्लंगम के लिए करार नहीं करेगा अन्यथा, कारबार के साधारण अनुक्रम में आस्तियों का विक्रय या व्ययन न हो; या

(ख) प्रस्ताव अवधि के दौरान मताधिकार बहन करने वाली प्राधिकृत किंतु अनिर्गमित प्रतिभूतियों का निर्गम नहीं करेगा;

(ग) कोई तार्त्विक संब्रिदाएं नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण:—उप-विनियम (1) के खंड (ख) के अधीन प्रतिभूतियों के निर्गम पर निबंधन संपरिवर्तन/विकल्प के प्रयोग के पूर्व अवधारित निबंधनों के अनुसार, पहले से ह² निर्गमित डिबेचरों के संपरिवर्तन पर या वारंटों के प्रति विकल्प का प्रयोग करने पर मताधिकार युक्त शेयरों को जारी और आबंटित करने के लिए लक्ष्य कंपनी के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा।

(2) लक्ष्य कंपनी अर्जनकर्ता को, अर्जनकर्ता के अनुरोध के 7 दिनों के भीतर या विनिर्दिष्ट तारीख से 7 दिनों के भीतर, जो भी बाद में है, शेयरधारकों या वारंटधारकों या संपरिवर्तनीय डिबेचरधारकों जो विनियम 22 के उप-विनियम (3) के स्पष्टीकरण (2) के अधीन सहभागिता के लिए पात्र है, नाम, पते, शेयरधारिता और फोलियो संख्या, और उन व्यक्तियों के जिनके शेयरों के अन्तरण के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन कंपनी के पास लंबित हैं, से युक्त एक सूची देगा।

(3) एक बार सार्वजनिक घोषणा हो जाने के बाद लक्ष्य कंपनी का निदेशक बोर्ड;—

(क) नीचे उप-विनियम (6) के अधीन यथा उपबंधित मर्जेंट बैंकर द्वारा प्रमाणीकरण की तारीख तक, अतिरिक्त निदेशक के तौर पर नियुक्ति या निदेशक बोर्ड का कोई प्राक-स्मिक रिक्त स्थान, अर्जनकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले या उसमें हित रखने वाले किसी व्यक्ति(यों) द्वारा नहीं भरेगा।

परन्तु यह प्रस्ताव के बद होने पर और शेयरधारकों को संदेय प्रतिकल की पूर्ण राशि का विशेष खाते में जमा होने पर, परिवर्तन जो अर्जनकर्ता को बोर्ड में प्रतिनिधित्व या कंपनी पर नियंत्रण देगे, लक्ष्य कंपनी द्वारा किए जा सकते हैं।

(ख) अर्जनकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले या उसमें हित रखने वाले किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को, यदि वह सार्वजनिक घोषणा की तारीख के पूर्व पहले से ही लक्ष्य कंपनी के बोर्ड में एक निदेशक है, प्रस्ताव से संबंधित किसी मामले में, जिसके अन्तर्गत उसकी ओर कोई प्रारंभिक कदम है, भाग लेने के लिए अनुज्ञात नहीं करेगा।

(4) लक्ष्य कंपनी का निदेशक बोर्ड, यदि वे ऐसी वांछा करते हैं, तो, शेयरधारकों को प्रस्ताव(वों) पर अपनी निष्पक्ष टिप्पणियां और सिफारिशें, शेयरधारकों के प्रांत निदेशकों की

वैश्वामिक जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए भेज सकेगा और इस प्रयोजन के लिए एक स्वतंत्र मर्चेट बैंककार या स्वतंत्र निदेशकों की समिति की राय मांग सकेगा ;

परन्तु यह कि किसी अशुद्ध कथन के लिए या तात्त्विक जानकारी के छिपाव के लिए, निदेशक इन विनियमों और अधिनियम के निबंधनों के अनुसार कार्रवाई के लिए दायी होंगे।

(5) लक्ष्य कंपनी का निदेशक बोर्ड स्वीकारोक्तियों के लिए पेश की गई प्रतिभूतियों के सत्यापन में अर्जनकर्ता को सुकर बनाएगा।

(6) विनियमों के अधीन अर्जनकर्ता द्वारा सभी बाध्यताओं को पूरा करने पर जैसा मर्चेट बैंककार द्वारा प्रमाणित किया जाए, लक्ष्य कंपनी का निदेशक बोर्ड अर्जनकर्ता द्वारा अर्जन प्रतिभूतियों, चाहे करार के अधीन या खुले बाजार क्रयों से हों, का अन्तर्गण अर्जनकर्ता के नाम में करेगा और, या निदेशक बोर्ड में ऐसे परिवर्तनों को अनुज्ञात करेगा, जो अर्जनकर्ता को बोर्ड में प्रतिनिधित्व या कंपनी पर नियंत्रण देंगे।

(7) विनियम 22 के उप-विनियम 16 में उपबंधित बाध्यताओं का पालन कंपनी द्वारा पालन उसमें विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में किया जाएगा।

मर्चेट बैंककार की सामान्य बाध्यताएं :—24 (1) इसके पूर्व कि प्रस्ताव की सार्वजनिक घोषणा की जाती है, मर्चेट बैंककार सुनिश्चित करेगा कि :—

(क) अर्जनकर्ता प्रस्ताव को कार्यान्वित करने में समर्थ है;

(ख) विनियम 28 में निर्दिष्ट निलंब खाते से संबंधित उपबंध कर दिया गया है;

(ग) प्रस्ताव के अधीन बाध्यताएं पूरी करने के लिए सत्यापन योग्य माध्यमों के माध्यम से संदाय के लिए निधियों और धन की पक्की व्यवस्थाएं की गई हैं;

(घ) विनियमों के निबंधनों के अनुसार प्रस्ताव की सार्वजनिक घोषणा की जाती है।

(2) मर्चेट बैंककार बोर्ड को एक सम्यक् तत्परता प्रमाणपत्र देगा जो प्रस्ताव पत्र के प्रारूप से संलग्न होगा।

(3) मर्चेट बैंककार सुनिश्चित करेगा कि सार्वजनिक घोषणा प्रारूप और प्रस्ताव पत्र बोर्ड, लक्ष्य कंपनी के पास दाखिल किया जाता है और उन सभी स्टॉक एक्सचेंजों को भी भेजा जाता है जिन पर लक्ष्य कंपनी के शेयर विनियमों के अनुसार सूचीबद्ध हैं।

(4) मर्चेट बैंककार सुनिश्चित करेगा कि प्रस्ताव की सार्वजनिक घोषणा और प्रस्ताव पत्र की भी विषय-वस्तु सत्य, श्रेष्ठ तथा पर्याप्त और विश्वसनीय स्रोतों पर आधारित है, स्रोत उल्कथित करते हुए जहां कहीं भी आवश्यक हो।

(5) मर्चेट बैंककार विनियमों और किन्हीं अन्य विधियों या नियमों जो इस संबंध में प्रयोज्य किए जाएं की अनुपालना सुनिश्चित करेगा।

(6) विनियमों के अधीन अर्जनकर्ताओं द्वारा सभी बाध्यताओं को पूरा करने पर, मर्चेट बैंककार बैंक से, जिसके साथ निलम्ब राशि जमा की गई है, अर्जनकर्ताओं को बाकी राशि निर्मावित करवायेगा।

(7) मर्चेट बैंककार बोर्ड को एक अन्तिम रिपोर्ट प्रस्ताव के बन्द होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर भेजेगा।

प्रतियोगी बोली :—25. (1) अर्जनकर्ता से भिन्न कोई व्यक्ति, जिसने पहली सार्वजनिक घोषणा की हो, जो कोई प्रस्ताव करना चाहता है, पहले प्रस्ताव की सार्वजनिक घोषणा के 21 दिनों के भीतर, उसी लक्ष्य कंपनी के शेयरों के अर्जन के लिए उसके प्रस्ताव की सार्वजनिक घोषणा करेगा।

स्पष्टीकरण : उपविनियम (1) के अधीन किया गया प्रस्ताव एक प्रतियोगी बोली समझा जाएगा।

(2) एक प्रस्ताव या प्रतियोगी बोली के लिए कोई सार्वजनिक घोषणा पहले प्रस्ताव की सार्वजनिक घोषणा की तारीख से 21 दिनों के पश्चात् नहीं की जाएगी।

(3) अर्जनकर्ताओं द्वारा कोई प्रतियोगी प्रस्ताव शेयरों की ऐसी संख्या के लिए किया जाएगा जो, जब उसके साथ सामान्य मति से कार्य करते हुए व्यक्तियों के साथ मिलकर उसके द्वारा धारित शेयरों के साथ इकट्ठे लिए गए, कम से कम शेयरों की उस संख्या के बराबर हो जाएंगे जिसके लिए पहली सार्वजनिक घोषणा की गई हो।

(4) प्रतियोगी बोली या बोलियों की सार्वजनिक घोषणा पर अर्जनकर्ता(ओं) जिसने पूर्वतर प्रस्ताव(वों) की सार्वजनिक घोषणा(णाएं) की थी, के पास—

(क) प्रस्ताव के पुनरीक्षण की घोषणा करने का विकल्प होगा; या

(ख) बोर्ड के पूर्वानुमोदन से, प्रस्ताव के प्रत्याहरण करने की घोषणा करने का विकल्प होगा।

परन्तु यह कि यदि प्रतियोगी बोली (बोलियों) की घोषणा के चौदह दिनों के भीतर कोई ऐसी घोषणा नहीं की जाती है, तो मूल निबंधनों पर पूर्वतर प्रस्ताव विधिमान्य रहेगा (रहेंगे) और अर्जनकर्ता(ओं) पर जिसने प्रस्ताव किया था (थे) बाध्यकारी होगा सिवाय इसके कि प्रस्ताव के बंद करने की तारीख अन्तिम अस्तित्वयुक्त प्रतियोगी बोली के अधीन सार्वजनिक प्रस्ताव के बन्द होने की तारीख तक विस्तारित रहेगी।

(5) इन विनियमों के उपबंध उप-विनियम (1) के अधीन की गई प्रतियोगी बोली (बोलियों) पर यथावश्यक परिवर्तन सहित प्रयोज्य होंगे।

(6) अर्जनकर्ता(ओं) जिन्होंने प्रतियोगी बोली(बोलियों) की सार्वजनिक घोषणा सहित प्रस्ताव(वों) की सार्वजनिक घोषणा कर दी है किन्तु उप-विनियम (4) के निबंधनों के अनुसार प्रस्ताव का प्रत्याहरण नहीं किया है के पास, प्रस्ताव के बंद होने की तारीख से पूर्व सात कार्य दिवसों तक किसी भी समय, अर्जित किए जाने वाले शेयरों की कीमत और संख्या की बाबत उनके प्रस्ताव(वों) में ऊर्ध्वमुखी संशोधनों को करने का विकल्प होगा :

परन्तु यह कि अर्जनकर्ता के पास उनके प्रस्ताव के किन्हीं अन्य निबंधनों और शर्तों को परिवर्तित करने का विकल्प नहीं होगा :

परन्तु यह और कि कोई ऐसा ऊर्ध्वमुखी पुनरीक्षण केवल तभी अर्जनकर्ता को किया जाएगा—

(क) ऐसे परिवर्तनों या संशोधनों की बाबत सार्वजनिक घोषणा उन सभी समाचारपत्रों में जिनमें मूल सार्वजनिक घोषणा की गई थी, करने पर;

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट सार्वजनिक घोषणा के जारी होने के एक साथ, बोर्ड, सभी स्टॉक एक्सचेंजों जिन पर कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, और लक्ष्य कंपनी को उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में सूचना देने पर;

(ग) विनियम 28 के उप-विनियम (9) के अधीन यथाउपबंधित निलम्ब खाते का मूल्य बढ़ाने पर।

(7) जहां प्रतियोगी बोली है, वहां मूल बोली के बंद होने की तारीख साथ ही सभी पश्चात्तर्ती प्रतियोगी बोलियों के बन्द होने की तारीख अन्तिम अस्तित्वयुक्त प्रतियोगी बोली के अधीन सार्वजनिक प्रस्ताव के बन्द होने की तारीख होगी और सभी अस्तित्वयुक्त बोलियों के अधीन सार्वजनिक प्रस्ताव उसी तारीख को बन्द होंगे।

प्रस्ताव का ऊर्ध्वमुखी पुनरीक्षण.—26. प्रतियोगी बोली है या नहीं का विचार किए बिना, अर्जनकर्ता जिसने प्रस्ताव का सार्वजनिक घोषणा कर दी हो, उसके प्रस्ताव में अर्जित किए जाने वाले शेयरों की कीमत और संख्या की बाबत ऊर्ध्व-मुखी पुनरीक्षणों को कर सकेगा, प्रस्ताव के बन्द होने की तारीख से पूर्व सात कार्य दिवसों तक किसी भी समय :

परन्तु यह कि प्रस्ताव का कोई ऐसा ऊर्ध्वमुखी पुनरीक्षण केवल तभी अर्जनकर्ता को किया जाएगा—

(क) ऐसे परिवर्तनों या संशोधनों की बाबत सार्वजनिक घोषणा उन सभी समाचारपत्रों में जिनमें मूल सार्वजनिक घोषणा की गई थी, करने पर;

(ख) ऐसी सार्वजनिक घोषणा के जारी होने के एक साथ, बोर्ड, सभी स्टॉक एक्सचेंजों जिन पर कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, और लक्ष्य कंपनी को उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में सूचना देने पर;

(ग) विनियम 28 के उप-विनियम (9) के अधीन यथा उपबंधित निलम्ब खाते का मूल्य बढ़ाने पर।

प्रस्ताव का प्रत्याहरण.—27. (1) निम्नलिखित परिस्थितियों के अलावा, एक बार किया गया, कोई सार्वजनिक प्रस्ताव, प्रत्याहृत नहीं किया जाएगा;

(क) प्रत्याहरण किसी प्रतियोगी बोली के परिणामस्वरूप है;

(ख) अपेक्षित कानूनी अनुमोदन(नों) को नामंजूर किया गया हो;

(ग) एकल अर्जनकर्ता की, जो व्यक्ति हो, मृत्यु हो गई हो;

(घ) ऐसी परिस्थितियां जो बोर्ड की राय में प्रत्याहरण के लिए योग्य हों।

(2) उप-विनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में से किसी के अधीन प्रस्ताव के प्रत्याहरण की दशा में, अर्जनकर्ता या सर्वेंट वैककार :

(क) एक सार्वजनिक घोषणा उन्हीं समाचारपत्र में जिनमें प्रस्ताव की सार्वजनिक घोषणा प्रकाशित की गई थी, प्रस्ताव के प्रत्याहरण के लिए कारणों को उपदेशित करते हुए करेगा।

(ख) ऐसी सार्वजनिक घोषणा जारी करने के एक साथ, (i) बोर्ड; (ii) सभी स्टॉक एक्सचेंजों जिन पर कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं; और (iii) लक्ष्य कंपनी को इसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में सूचित करेगा।

निलम्ब का उपबंध.—28. (1) अर्जनकर्ता विनियमों के अधीन उसकी बाध्यताओं के पालन के लिए प्रतिभूति के रूप में और के तौर पर, उप-विनियम 2 में यथाविनिर्दिष्ट ऐसी राशि एक निलम्ब खाते में जमा करेगा।

(2) निलम्ब खाते की गणना, निम्नलिखित रीति में की जाएगी,—

(क) सार्वजनिक प्रस्ताव के अधीन संदेय प्रतिफल के लिए—

100 करोड़ रु. तक और सहित	— 25 %
100 करोड़ रु. से अधिक	— 25 %
100 करोड़ रुपये तक और उसके बाद	— 10 %

(ख) उन प्रस्तावों के लिए जो स्वीकृति के किसी न्यूनतम स्तर के अधधीन हैं, और अर्जनकर्ता न्यूनतम 20 प्रतिशत अर्जित नहीं करना चाहता है, तब सार्वजनिक प्रस्ताव के अधधीन संदेय प्रतिफल का 50 प्रतिशत, नकद रूप में निलम्ब खाते में जमा किया जाएगा।

(3) सार्वजनिक प्रस्ताव के अधधीन संदेय कुल प्रतिफल की गणना पूर्ण स्वीकारोक्तियों की कल्पना करते हुए, और उच्चतम कीमत पर की जाएगी यदि प्रस्ताव अन्तरीय कीमत-निर्धारण के अधधीन है, प्रस्ताव के लिए प्रतिफल नकद रूप में या से अन्यथा संदेय है का विचार किए बिना।

(4) उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट निलम्ब खाता निम्न में गठित होगा,

(क) अनुसूचित वाणिज्य बैंक के पास नकद जमाराशि; या

(ख) मर्चेट बैंककार के पक्ष में बैंक गारंटी; या

(ग) मर्चेट बैंककार के पास, समुचित भाजित के साथ जमा स्वीकार्य प्रतिभूतियाँ।

या

(घ) नकद, इस विनियम के उप-विनियम (2) के खंड (ख) के मामले में किसी अनुसूचित वाणिज्य बैंक के पास जमा।

(5) जहाँ निलम्ब खाता किसी अनुसूचित वाणिज्य बैंक के पास जमाराशि के रूप में है, वहाँ अर्जनकर्ता, खाता खोलते समय, प्रस्ताव के लिए नियुक्त मर्चेट बैंककार को विनियमों में यथा उपबंधित निलम्ब खाते में जमाराशि के लिए एक बैंकर चैक या मांगदेय ड्राफ्ट जारी करने के लिए बैंक को अनुरोध देने के लिए सशक्त करेगा।

(6) जहाँ निलम्ब खाता बैंक गारंटी से मिलकर बना है, ऐसी बैंक गारंटी मर्चेट बैंककार के पक्ष में होगी और प्रस्ताव के बंद होने के पश्चात् 30 दिनों तक सार्वजनिक घोषणा की तारीख से प्रारम्भ होने वाली कम से कम किसी अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

(7) अर्जनकर्ता, निलम्ब खाने में प्रतिभूतियों के रूप में होने की दशा में मर्चेट बैंककार को ऐसे निलम्ब खाते के मूल्य को विज्ञापन द्वारा या से अन्यथा वसूल करने के लिए सशक्त करेगा परन्तु यह कि यदि प्रतिभूतियों के मूल्य की वसूली पर कोई कमी है, तो मर्चेट बैंककार किसी ऐसी कमी को पूरा करने के लिए दायी होगा।

(8) निलम्ब खाते के बैंक गारंटी या अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में होने की दशा में, इन्हे विनियमों के अधीन सभी बाध्यताओं के पूरा होने के पश्चात् तक मर्चेट बैंककार द्वारा लौटाया नहीं जाएगा।

(9) किसी प्रतियोगी बोली होने के परिणामस्वरूप या अन्यथा प्रस्ताव का कोई उध्वंमुखी पुनरीक्षण किए जाने की दशा में, निलम्ब खाते का मूल्य ऐसा पुनरीक्षण करने पर संदेय प्रतिफल के कम से कम 10 प्रतिशत के बराबर करने के लिए बढ़ाया जाएगा।

(10) जहाँ निलम्ब खाता बैंक गारंटी या निश्चित अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में है, वहाँ अर्जनकर्ता संदेय कुल प्रतिफल की कम से कम 1 प्रतिशत की राशि भी बैंक के पास जमा करेगा, अर्जनकर्ता(ओं) द्वारा विनियमों के अधीन बाध्यताओं के पूरा करने के लिए प्रतिभूति के रूप में और के तौर पर।

(11) बोर्ड, अर्जनकर्ता द्वारा विनियमों के अधीन बाध्यताओं के पूरा न किए जाने की दशा में निलम्ब खाते का या तो पूर्णतः या अंशतः समपहरण करेगा।

(12) बैंक के पास नकद रूप में जमा किया गया निलम्ब खाता केवल निम्नलिखित रीति में निमोचित किया जाएगा,—

(क) मर्चेट बैंककार द्वारा प्रमाणीकरण करने पर विनियम 27 के निबंधनों के अनुसार प्रस्ताव का प्रत्याहरण करने पर अर्जनकर्ता को कुल राशि;

(ख) विनियम 29 के उपविनियम (1) के निबंधनों के अनुसार खोले गए विशेष खाते में अन्तरण के लिए;

परन्तु इस प्रकार अन्तरित राशि इस विनियम के उप-विनियम (2) के खंड (क) के अधीन की गई नकद जमाराशि की 90 प्रतिशत से अधिक होगी।

(ग) अर्जनकर्ता को, विनियमों के अधीन सभी बाध्यताओं के पूरा करने पर, मर्चेट बैंककार द्वारा प्रमाणीकरण करने पर, इस विनियम के उप-विनियम (2) के खंड (क) के अधीन की गई नकद जमाराशि या इस विनियम के उप-विनियम (8) के अधीन की गई नकद जमाराशि के बाकी 10 प्रतिशत;

(घ) विनियमों के अधीन सभी बाध्यताओं के पूरा करने पर अर्जनकर्ता को कुल राशि, मर्चेट बैंककार द्वारा प्रमाणीकरण करने पर, जहाँ प्रस्ताव जेयरो या अन्य प्रतिभूत निम्नतों के विनियम के लिए है;

(ङ) मर्चेट बैंककार को कुल राशि, विनियमों के अधीन बाध्यताओं में से किसी के पूरा न करने के लिए समपहरण की दशा में, मर्चेट बैंककार और प्रस्ताव के रजिस्ट्रारों के व्ययों यदि कोई हों, ही कटौती के पश्चात् लक्ष्य कंपनी, प्रादेशिक स्टॉक एक्सचेंज और शेयरधारकों को जिन्होंने प्रस्ताव स्वीकार किया था के बीच निम्न रीति से वितरण के लिए—

(i) राशि का एक तिहाई लक्ष्य कंपनी को;

(ii) राशि का एक तिहाई प्रादेशिक स्टॉक एक्सचेंज को विनिधानकर्ता संरक्षण निधि या विनिधानकर्ता शिक्षा, अनुसंधान, शिकायत समाधान के लिए किसी अन्य ऐसी ही निधि में जमा करने के लिए और ऐसे समरूप प्रयोजनों के लिए, जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएं;

(iii) अवशिष्ट एक तिहाई उन शेयरधारकों के बीच अनुपाततः वितरित किए जाने के लिए जिन्होंने प्रस्ताव स्वीकार किया है।

(13) अर्जनकर्ता द्वारा बाध्यताओं के पूरा न करने की दशा में, मर्चेट बैंककार जमाराशि के पुरोबंध, बैंक गारंटी का अवलंबन लेते, या प्रतिभूतियों के विज्ञापन के रूप में निलम्ब खाते की वसूली सुनिश्चित करेगा और लक्ष्य कंपनी के उसकी आगमों को प्रादेशिक स्टॉक एक्सचेंज को जमा करेगा, विनि-

धानकर्ता संरक्षण निधि या किसी अन्य ऐसी ही निधि में जमा करने के लिए।

प्रतिफल का संशय :—29 (1) तकद में संशय प्रतिफल की राशि के लिए, अर्जनकर्ता, प्रस्ताव के बंद होने की तारीख से 21 दिनों की अवधि के भीतर, बोर्ड में रजिस्ट्रीकृत एक निर्गम बैंककार के साथ एक विशेष खाता खोलेगा और उसमें, ऐसी राशि जमा करेगा, जो निलंब खाते में पड़ी राशि, यदि कोई हो, के 90% के साथ मिलकर, इन विनियमों के निबंधनों के अनुसार प्राप्त और स्वीकृत स्वीकारोक्तियों के लिए, प्रतिफल के रूप में शोध्य और संदेय कुल राशि पूरी करेगी और इस प्रयोजन के लिए, निलंब खाते में निधियों का अन्तरण करेगा।

(2) उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट खाते में जमा पड़े आवश्यकत अतिशेष को उसके जमा होने की तारीख से 3 वर्षों की समाप्ति पर लक्ष्य कंपनी के प्रादेशिक स्टॉक एक्सचेंज की विनिधानकर्ता संरक्षण निधि में अन्तरित किया जाएगा।

(3) प्रतिभूतियों के विनियम के रूप में संशय प्रतिफल की बाबत, अर्जनकर्ता सुनिश्चित करेगा कि प्रतिभूतियां वास्तव में निर्गमन और शेयरधारकों को प्रेषित की जाती हैं।

अध्याय IV

उपनिहित अधिग्रहण

उपनिहित अधिग्रहण :—30 (1) इस अध्याय के उपबंध, एक लोक वित्तीय संस्था या एक अनुसूचित बैंक, (इसमें इसके पश्चात् अग्रणी संस्था के रूप में निर्दिष्ट) द्वारा अनुमोदित पुनर्वास की स्कीम के अनुसरण में, एक वित्तीय रूप से दुर्बल कम्पनी, जो एक दृग्न औद्योगिक कम्पनी न हो, के शेयरों के पर्याप्त अर्जन पर लागू होंगे।

(2) अग्रणी संस्था इस अध्याय के उपबंधों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगी।

(3) अग्रणी संस्था वित्तीय लाभप्रदता पर विचार करते हुए वित्तीय रूप से दुर्बल कम्पनी का अंकन करेगी, और पुनः प्रवर्तन के लिए निधियों की आवश्यकता का निर्धारण करेगी तथा अल्पमत शेयरधारकों के हितों का संरक्षण समुचित प्रबंध प्रभावी पुनरुज्जीवन और पारदर्शिता के सिद्धान्त पर पुनर्वास पैकेज तैयार करेगी।

(4) पुनर्वास स्कीम प्रबन्ध तंत्र में किसी परिवर्तन के व्यौरों का विनिर्दिष्ट रूप से उपबन्ध भी करेगी।

(5) स्कीम निम्नलिखित किसी भी रीति से वित्तीय रूप से दुर्बल कम्पनी में शेयरों के अर्जन का उपबन्ध कर सकेगी :—

- (क) शेयरों का एकमुश्त क्रय; या
- (ख) शेयरों का विनिमय; या
- (ग) दोनों का संयोजन।

परन्तु यह कि स्कीम यथामंजूर यह सुनिश्चित कर सकेगी कि प्रस्तावित अर्जन के पश्चात् पहले के संप्रवर्तकों के स्वामित्व में कोई शेयर नहीं रहता है, यदि ऐसी स्कीम के अनुसरण में नए संप्रवर्तकों द्वारा ऐसा अर्जन किया जाता है।

स्पष्टीकरण : इस अध्याय के प्रयोजन के लिए “वित्तीय रूप से दुर्बल कम्पनी” पद से वह कम्पनी अभिप्रेत है जिसकी पूर्व वित्तीय वर्ष के अंत में संचित हानियां, जो पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ पर इसके शुद्ध मूल्य अर्थात् समादत्त पूंजी और खुली आरक्षितियों की कुल राशि के 50% से अधिक परन्तु 100% से कम के त्वास में परिणामित हुई हो।

शेयरों के अर्जन की रीति :— 31 (1) अग्रणी संस्था पुनर्वास की किसी स्कीम को कार्यान्वित करने से पूर्व कम से कम तीन पक्षकारों से शेयरों के अर्जन के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करेगी।

(2) उप-विनियम (1) के अधीन प्रस्तावों की प्राप्ति के पश्चात् अग्रणी संस्था वित्तीय रूप से दुर्बल कम्पनी का पुनर्वास करने के लिए शेयरों का अर्जन करने वाले व्यक्ति की प्रबंधकीय क्षमता, वित्तीय संसाधनों की पर्याप्तता और तकनीकी सामर्थ्य को ध्यान में रखते हुए पक्षकारों में से किसी एक का चयन करेगी।

(3) अग्रणी संस्था, शेयरों के अर्जन का प्रस्ताव करने का इरादा रखने वाले किसी व्यक्ति को वित्तीय रूप से दुर्बल कम्पनी के बारे में आवश्यक जानकारी उपलब्ध करायेगी और विनिर्दिष्ट: इसके वर्तमान प्रबंध, तकनीक, विनिर्मित उत्पादों की श्रेणी, शेयरधारिता क्रम, वित्तीय धारिता और कार्य-निष्पादन और प्रस्ताव की तारीख से पिछले पांच वर्ष की अवधि का समावेश करते हुए ऐसी कम्पनी की आस्तियां और देयताएं साथ ही ऐसे पुनर्वास के लिए शेयरों का अर्जन करने वाले व्यक्ति से अपेक्षित न्यूनतम वित्तीय और अन्य प्रनिबद्धताओं के संबंध में।

बोलियों के मूल्यांकन की रीति :—32 (1) अग्रणी संस्था क्रय कीमत या शेयरों के विनिमय, पिछले कार्य-निष्पादन रिकार्ड, वित्तीय संसाधनों, शेयरों का अर्जन करने वाले व्यक्ति के प्रबंध की ख्याति की बाबत प्राप्त बोलियों का मूल्यांकन करेगी और प्रक्रिया में औचित्य और पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी।

(2) उप-विनियम (1) में यथा उपबंधित मूल्यांकन करने के पश्चात् प्राप्त प्रस्तावों को अधिमान-क्रम में सूचीबद्ध किया जाएगा और वित्तीय रूप से दुर्बल कम्पनी के प्राबधिक कार्यकलाप करने वाले व्यक्तियों से परामर्श के पश्चात् इन बोलियों में से एक को स्वीकार किया जाएगा।

शेयरों का अर्जन करने वाला व्यक्ति - प्रस्ताव करना

33. शेयरों का अर्जन करने वाला व्यक्ति, जिसे विनियम 32 के उप-विनियम 2 के अधीन अग्रणी संस्था द्वारा परिलक्षित कर लिया गया हो, इस निमित्त अग्रणी संस्था से संसूचना की प्राप्ति पर संप्रवर्तकों या वित्तीय

रूप में दुर्बल कम्पनी के प्राधिकृत कार्यकर्ताओं के प्रभारी व्यक्तियों, वित्तीय संस्थाओं से तथा कम्पनी के अन्य शेयरधारकों से भी शेयरों का अर्जन करने वाले व्यक्ति और अग्रणी संस्था, या और कम्पनी या कानूनी द्वारा एक निश्चित कीमत पर शेयरों के अर्जन के लिए औपचारिक प्रस्ताव करेगा।

स्पष्टीकरण 3—इस विनियम में कुछ भी, अग्रणी संस्था को वित्तीय रूप में दुर्बल कम्पनी में पुनर्जीवनीयता के भाग रूप इसके द्वारा धारित शेयरधारिताओं को प्रस्तुत करने का प्रतिषेध नहीं करेगा।

शेयरों का अर्जन करने वाला व्यक्ति - सार्वजनिक घोषणा करना - 34. (1) संप्रवर्तकों या वित्तीय रूप से दुर्बल कम्पनी के प्राधिकृत कार्यकर्ताओं के प्रभारी व्यक्तियों या वित्तीय संस्था में शेयरों का अर्जन करने वाला व्यक्ति कम्पनी के अन्य शेयरधारकों से शेयरों के अर्जन के लिए अपने आशय की एक सार्वजनिक घोषणा करेगा।

(2) ऐसी सार्वजनिक घोषणा में शेयरों का अर्जन करने वाले व्यक्ति की पहचान और पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी, अर्जित किए जाने के लिए प्रस्तावित शेयरों की संख्या और प्रतिशतता, प्रस्ताव कीमत, विनिर्दिष्ट तारीख, प्रस्ताव के खुलने की तारीख और वह अवधि जिसके लिए प्रस्ताव को खूला रखा जाएगा और ऐसे अन्य विवरण जो बोर्ड द्वारा अपेक्षित किए जाएं, को सम्मिलित करते हुए, प्रस्ताव के बारे में सुसंगत व्यौरें अंतर्विष्ट होंगी।

(3) प्रस्ताव पत्र, संप्रवर्तकों या वित्तीय रूप से दुर्बल कम्पनी के प्रबंध के प्रभारी व्यक्तियों और वित्तीय संस्थाओं से भिन्न शेयरधारकों में से प्रत्येक को भेजा जाएगा।

(4) यदि उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट प्रस्ताव का परिणाम सार्वजनिक शेयरधारिता में कम्पनी की मतदाता पूंजी का 10% या न्यून तक घटना हो, अर्जनकर्ता या तो-

(क) सार्वजनिक प्रस्ताव के बंद होने की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर, शेयरधारकों के पास रखे शेष बकाया शेयरों का उसी पारदा कीमत पर खरीद करने के लिए प्रस्ताव करेगा, जिसका प्रभाव लक्ष्य कम्पनी का असूचीकरण हो, या

(ख) या विशय के लिए एक प्रस्ताव के माध्यम से या जनता को पूंजी के एक नए निर्गम द्वारा, जो सार्वजनिक प्रस्ताव के बंद होने की तारीख से 6 मास की अवधि के भीतर खुलता, शेयरों की ऐसी संख्या का विनिवेश करने का वचन देगा ताकि पूंजीकरण प्रेषण पूर्ण हो सकें।

(5) प्रस्ताव पत्र में उप-विनियम (4) के अधीन अर्जनकर्ता को उपररूप विकल्प का स्पष्ट रूप में कथन होगा।

(6) उप-विनियम (4) में निर्दिष्ट प्रतिशतता को गणना करते के प्रयोजनों के लिए, सार्वजनिक प्रस्ताव

का बंद होने के पश्चात् तीस दिनों की समाप्ति पर गता-भित्तियों की गणना की जाएगी।

(7) संप्रवर्तकों या वित्तीय रूप से दुर्बल कम्पनी के प्रभारी व्यक्तियों या वित्तीय संस्थाओं से भिन्न शेयरधारकों से प्रस्ताव स्वीकार करने समय, शेयरों का अर्जन करने वाला व्यक्ति, व्यक्तिगत शेयरधारक में उनकी पूर्ण सारधारिताओं को अर्जित करने का प्रभाव करेगा, यदि ऐसी धारिता दस रुपये प्रत्येक के अर्जित मुख्य वाले सौ शेयरों तक या सौ रुपये प्रत्येक के अर्जित मुख्य के दस शेयरों तक है।

प्रतियोगी बोली :- 35. कोई व्यक्ति वित्तीय रूप से दुर्बल कम्पनी के शेयरों के अर्जन के लिए प्रतियोगी बोली नहीं लगाएगा जब एक बार अग्रणी संस्था ने बोली का मूल्यांकन कर लिया हो और उस अर्जनकर्ता को बोली स्वीकार कर ली हो, जिसने संप्रवर्तकों या वित्तीय रूप से दुर्बल कम्पनी के प्रबंध के प्रभारी व्यक्तियों से भिन्न शेयरधारकों से शेयरों के अर्जन के लिए प्रस्ताव की सार्वजनिक घोषणा कर दी हो।

अध्याय III के प्रवर्तनों से छूट--36. (1) प्रत्येक प्रस्ताव जो विनियम 30 के अन्वय में तैयार किया गया है, बोर्ड को इन विनियमों के अध्याय III के उपबंधों से ऐसे अर्जनों को छूट प्रदान करने के लिए आदेश के साथ भेजा जाएगा।

(2) ऐसे अनुरोध पर विचार करने के लिए, बोर्ड, कम्पनी तथा अग्रणी संस्था में भी, प्रस्तावों की जांच करने की रीति, ऐसे प्रस्तावों के मूल्यांकन और ऐसे ही अन्य मामलों से संबंधित ऐसी जानकारी मांग सकेंगे।

(3) बोर्ड द्वारा छूट के होने हुए भी, अग्रणी संस्था या अर्जनकर्ता यथाशक्य शीघ्र, अध्याय III में विनिर्दिष्ट सार्वजनिक प्रस्ताव के लिए विभिन्न क्रियाकलापों के लिए विनिर्दिष्ट समय-सीमाओं का पालन करेगा।

एक राज्य स्तरीय लोक वित्तीय संस्था तथा शेयरों का अर्जन--37. जहां पितृत्व रूप से दुर्बल कम्पनी की बाजार शेयरों के अर्जन के लिए प्रस्ताव एक राज्य स्तरीय लोक वित्तीय संस्था द्वारा दिया गया है, वहां इन विनियमों के के उपबंध बंधे ही लागू होंगे जैसे कि एक लोक वित्तीय संस्था द्वारा संचार की गई पत्रवात स्कीम में संबंधित, सिवाय इसके कि यदि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, राष्ट्रीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 के अधीन स्थापित एक निगम, वित्तीय रूप से दुर्बल कम्पनी में शेयरों के अर्जन के लिए इन विनियमों की अनुपादना सुनिश्चित करने के लिए एजेंसी होंगी।

अध्याय 5

बोर्ड द्वारा अन्वेषण और कार्यवाही

बोर्ड का अन्वेषण करने का अधिकार—38. (1) बोर्ड, निम्नलिखित किन्हीं प्रयोजनों के लिए अन्वेषण करने के लिए एक या अधिक व्यक्तियों को अधिवेषण अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगा, अर्थात्:—

(क) शेयरों के पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण के अभिकर्तों से संबंधित किसी मामले पर विनिधानकर्ताओं, मध्यस्थियों या किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त शिकायतों का अन्वेषण करना ;

(ख) विनियमों के किसी भंग के लिए, प्रतिभूति बाजार के हित में या विनिधानकर्ताओं के हितों में इसके अपने ज्ञान या जानकारी पर स्वप्रेरणा से अन्वेषण करना ;

(ग) यह अभिनिश्चित करना कि क्या अधिनियम और विनियमों के उपबंधों का अनुपालन किया जा रहा है ।

अन्वेषण के पूर्व सूचना —39. (1) विनियम 38 के अधीन अन्वेषण का आदेश देने के पूर्व बोर्ड यथास्थिति, अर्जनकर्ता, विक्रेता, लक्ष्य कम्पनी, मर्जेंट बैंककार को कम से कम 10 दिनों की सूचना देगा ।

(2) उप-विनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां बोर्ड का यह समाधान हो जाता है कि विनिधानकर्ताओं के हित में ऐसी कोई सूचना नहीं दी जानी चाहिए, वहां वह, लिखित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा अन्वेषण ऐसी सूचना के बिना किया जाए ।

(3) अन्वेषण के दौरान, अर्जनकर्ता, विक्रेता, लक्ष्य कम्पनी, मर्जेंट बैंककार, जिनके विरुद्ध अन्वेषण किया जा रहा है विनियम 40 में यथा उपबंधित अपनी बाध्यता का निर्वाहन करने के लिए आबद्ध होगा ।

बोर्ड द्वारा अन्वेषण पर बाध्यताएं—40. (1) उम अर्जनकर्ता, विक्रेता, लक्ष्य कम्पनी, मर्जेंट बैंककार का, जिनके कामकाज का अन्वेषण किया जा रहा है और उसके प्रत्येक निदेशक, अधिकारी और कर्मचारी का यह कर्तव्य होगा कि इसकी अभिरक्षा या नियंत्रण में ऐसी बहियां, प्रतिभूतियां, लेखे, अभिलेख और अन्य दस्तावेज अन्वेषण अधिकारी को पेश करे और उसे अपने क्रियाकलापों से संबंधित ऐसे विवरण और जानकारी, जिसकी निरीक्षण अधिकारी अपेक्षा करे, ऐसी युक्तियुक्त अवधि के भीतर दे जो अन्वेषण अधिकारी विनिर्दिष्ट करे ।

(2) अर्जनकर्ता, विक्रेता, लक्ष्य कम्पनी, मर्जेंट बैंककार और व्यक्तियों जिनका अन्वेषण किया जा रहा है, अन्वेषण अधिकारी को ऐसे परिसर, जो उसके या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति के अधिभोग में हो, तक युक्तियुक्त पहुंच रखने की अनुज्ञा देंगे और अर्जनकर्ता, विक्रेता, लक्ष्य कम्पनी मर्जेंट बैंककार या ऐसे अन्य व्यक्ति के कब्जे में किन्हीं बहियों,

अभिलेखों, दस्तावेजों और कम्प्यूटर आंकड़ों की परीक्षा करने के लिए युक्तियुक्त सुविधा भी प्रदान करेंगे और दस्तावेजों या अन्य सामग्री को प्रतियां भी देंगे, जो अन्वेषण अधिकारी की राय में अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए सुसंगत हैं ।

(3) अन्वेषण अधिकारी, अन्वेषण के दौरान, अर्जनकर्ता, विक्रेता, लक्ष्य कम्पनी, मर्जेंट बैंककार के किसी निदेशक, अधिकारी या कर्मचारी की परीक्षा करने या कथन अभिलिखित करने का हक्कादार होगा ।

(4) अर्जनकर्ता, विक्रेता, लक्ष्य कम्पनी के मर्जेंट बैंककार के प्रत्येक निदेशक, अधिकारी या कर्मचारी का यह कर्तव्य होगा कि अन्वेषण अधिकारी को अन्वेषण के संबंध में वह सभी सहायता दे, जिसका अन्वेषण अधिकारी युक्तियुक्त रूप में अपेक्षा करे ।

बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत करना — 41. अन्वेषण अधिकारी, यथासंभव शीघ्र, अन्वेषण पूर्ण होने पर, बोर्ड को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ;

परन्तु यह कि यदि बोर्ड द्वारा ऐसा करने का निर्देश दिया जाए, तो वह अंतरिम रिपोर्टों को प्रस्तुत कर सकेगा ।

निष्कर्षों की संसूचना — 42. (1) बोर्ड, विनियम 41 में निर्दिष्ट अन्वेषण रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यथास्थिति अर्जनकर्ता, विक्रेता, लक्ष्य कम्पनी, मर्जेंट बैंककार को अन्वेषण अधिकारी के निष्कर्ष संसूचित करेगा, और उसे सूने जाने का एक अवसर देगा ।

(2) अर्जनकर्ता, विक्रेता, लक्ष्य कम्पनी, मर्जेंट बैंककार, यथास्थिति, से उत्तर की प्राप्ति पर, यदि कोई हो, यथास्थिति, बोर्ड उनसे ऐसे उपाय करने की अपेक्षा कर सकेगा जो बोर्ड प्रतिभूति बाजार के हित में और अधिनियम और इसके विनियमों के उपबंधों को सम्यक् अनुपालना के लिए ठीक समझे ।

लेखापरीक्षण की नियुक्ति — 43. इस विनियम में किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड सम्बद्ध व्यक्ति की लेखा बहियों या कामकाज का अन्वेषण करने के लिए एक अर्हित लेखापरीक्षक नियुक्त कर सकेगा ।

परन्तु यह कि इस प्रकार नियुक्त लेखापरीक्षक के पास अन्वेषण प्राधिकारी की वही शक्तियां होंगी जो विनियम 38 में कथित है और विनियम 40 में सम्बद्ध व्यक्ति की बाध्यताएं इस विनियम के अधीन अन्वेषण पर लागू होंगी ।

बोर्ड द्वारा निदेश—44. बोर्ड, प्रतिभूति बाजार के हितों में, अधिनियम की धारा 24 के अधीन आपराधिक अभियोजन सहित कार्यवाही आरम्भ करने के इसके अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे निदेश दे सकेगा जो यह ठीक समझे, जिसके अन्तर्गत निम्न है :

(क) व्यक्ति संबद्ध को प्रतिभूतियों में आने व्योहार न करने का निदेश देना ;

(ख) व्यक्ति संबद्ध को इन विनियमों के अतिक्रमण में अर्जित किन्हीं प्रतिभूतियों के व्ययन से प्रतिषेध करना;

(ग) व्यक्ति संबद्ध को इन विनियमों के उपबंधों के अतिक्रमण में अर्जित शेयरों का विक्रय करने का निदेश देना;

(घ) व्यक्ति संबद्ध के विरुद्ध कार्रवाई करना ।

अनुपालन के लिए शास्तियाँ—45 (1) कोई व्यक्ति, विनियमों के किन्हीं उपबंधों का अतिक्रमण करने पर विनियमों और अधिनियम के निबंधनों के अनुसार कार्रवाई के लिए दायी होगा ।

(2) यदि अर्जनकर्ता या उसके साथ सामान्य मति से कार्य करता हुआ कोई व्यक्ति, विनियमों के अधीन बाध्यताओं का पालन करने में असफल रहता है, निलंब खाते में राशि का कुल या भाग समाहृत किए जाने के लिए दायी होगा और विनियमों और अधिनियम के निबंधनों के अनुसार कार्रवाई के लिए भी दायी होगा ।

(3) विनियमों के अधीन बाध्यताओं का पालन करने में असफल होने पर लक्ष्य कम्पनी का निदेशक बोर्ड विनियमों और अधिनियम के निबंधनों के अनुसार कार्रवाई के लिए दायी होगा ।

(4) बोर्ड, एक मध्यवर्ती द्वारा विनियमों की अपेक्षाओं के पालन में असफलता के लिए, अधिनियम की धारा 12 के अधीन एक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र धारण करने वाले एक मध्यवर्ती के रजिस्ट्रीकरण के निलंबन या रद्दकरण के लिए कार्रवाई आरम्भ कर सकेगा ।

परन्तु यह कि रजिस्ट्रीकरण का कोई ऐसा प्रमाणपत्र तब तक निलंबित या रद्द नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे मध्यवर्ती पर लागू होने वाले विनियमों में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन न किया गया हो ।

(5) शेयरधारकों को किसी अशुद्ध कथन के लिए या शेयरधारकों को प्रकट किए जाने के लिए अपेक्षित तात्त्विक जानकारी के छिपावों के लिए, अर्जनकर्ता या निदेशकों जहां अर्जनकर्ता एक निगमित निज़ाय है, लक्ष्य कम्पनी के निदेशक, सार्वजनिक प्रस्ताव के मर्जेंट बैंककार और स्वतंत्र सलाह के लिए लक्ष्य कम्पनी द्वारा नियुक्त मर्जेंट बैंककार विनियमों और अधिनियम के निबंधनों के अनुसार कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे ।

(6) उप-विनियम (1) में (5) में निर्दिष्ट शास्तियों, में—

(क) अधिनियम की धारा 24 के अधीन आपराधिक अभियोजन ;

(ख) अधिनियम की धारा 15ज के अधीन आर्थिक शास्तियाँ;

(ग) अधिनियम की धारा 11ख के उपबंधों के अधीन निदेश सम्मिलित हैं ।

केन्द्रीय सरकार को अपील—46. इन विनियमों के अधीन बोर्ड के आदेश द्वारा व्यथित होने वाला कोई व्यक्ति केन्द्रीय सरकार को अपील कर सकेगा ।

निरसन और व्यावृत्ति—47. (1) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 1993 एतद्वारा निरमित किए जाने हैं ।

(2) ऐसे निरसन के होने हुए भी—

(क) की गई कोई बात या की गई या किए या लिए जाने के लिए तात्पर्यित कोई कार्रवाई जिसके अन्तर्गत कथित विनियमों के अधीन प्रस्ताव पत्र का अनुमोदन, प्रदत्त छूट, मंजूरित फोन कोई व्यापनिर्णयन जांच या प्रारम्भ किया गया अन्वेषण या जारी की गई कारण बताओं भूचना है, इन विनियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किए हुए समझे जाएंगे ।

(ख) कथित विनियमों के अधीन बोर्ड को किया गया और इसके समक्ष लंबित कोई आवेदन इन विनियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया हुआ समझा जाएगा ।

(ग) कथित विनियमों के अधीन केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत और इसके समक्ष लंबित किन्हीं अपीलों को इन विनियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया हुआ समझा जाएगा ।

[फा०स० भाप्रविबो/विधि/XVII/1/541/97]

देवेन्द्र राज मेहता, अध्यक्ष

भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

(Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 1997

NOTIFICATION

Mumbai, the 20th February, 1997

S.O. 124(E).—In exercise of the powers conferred by section 30 of the Securities and Exchange Board of India, Act 1992, (15 of 1992), the Board hereby makes the following Regulations, namely :—

CHAPTER 1

Preliminary

1. Short title and commencement.—(1) These Regulations shall be called the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 1997.

(2) These Regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—(1) In these Regulations, unless the context otherwise requires :—

(a) "Act" means the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992);

(b) "acquirer" means any person who, directly or indirectly, acquires or agrees to acquire shares or voting rights in the target company, or acquires or agrees to acquire control over the target company, either by himself or with any person acting in concert with the acquirer;

(c) "control" shall include the right to appoint majority of the directors or to control the management or policy decisions exercisable by a person or persons acting individually or in concert, directly or indirectly, including by virtue of their shareholding or management rights or shareholders agreements or voting agreements or in any other manner;

(d) "investigating officer" means any person appointed by the Board under Regulation 38;

(e) "person acting in concert" comprises,—

(1) persons who, for a common objective or purpose of substantial acquisition of shares or voting rights or gaining control over the target company, pursuant to an agreement or understanding (formal or informal), directly or indirectly co-operate by acquiring or agreeing to acquire shares or voting rights in the target company or control over the target company.

(2) Without prejudice to the generality of this definition, the following persons will be deemed to be persons acting in concert with other persons in the same category, unless the contrary is established :

- (i) a company, its holding company, or subsidiary of such company or company under the same management either individually or together with each other ;
- (ii) a company with any of its directors, or any person entrusted with the management of the funds of the company;
- (iii) directors of companies referred to in sub-clause (i) of clause (2) and their associates.
- (iv) mutual fund with sponsor or trustee or asset management company;
- (v) foreign institutional investors with sub account(s);
- (vi) merchant bankers with their client(s) as acquirer;
- (vii) portfolio managers with their client(s) as acquirer ;
- (viii) venture capital funds with sponsors;
- (ix) banks with financial advisers, stock brokers of the acquirer, or any company which is a holding company, subsidiary or relative of the acquirer.

Provided that sub-clause (ix) shall not apply to a bank whose sole relationship with the acquirer or with any company, which is a holding company or a subsidiary of the acquirer or with a relative of the acquirer, is by way of providing normal commercial banking services or such activities in connection with the offer such as confirming availability of funds, handling acceptances and other registration work.

(x) any investment company with any person who has an interest as director, fund manager, trustee, or as a shareholder having not less than 2 per cent of the paid-up capital of that company or with any other investment company in which such person or his associate holds not less than 2 per cent of the paid up capital of the latter company.

Note : For the purposes of this clause "associate" means :—

(a) any relative of that person within the meaning of section 6 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956); and

(b) family trusts and Hindu Undivided Families.

(f) "offer period" means the period between the date of public announcement of the first offer and the date of closure of that offer .

(g) "panel" means a panel constituted by the Board for the purpose of Regulation 4;

(h) "promoter" means

(1)(i) the person or persons who are in control of the company, or

(ii) person or persons named in any offer document as promoters;

(2) a relative of the promoter within the meaning of section 6 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) ; and

(3) in case of a corporate body,

(i) a subsidiary or holding company of that body, or

(ii) any company in which the 'Promoter' holds 10 per cent or more of the equity capital or which holds 10% or more of the equity capital of the Promoter, or

(iii) any corporate body in which a group of individuals or corporate bodies or combinations thereof who hold 20% or more of the equity capital in that company also hold 90% or more of the equity capital of the 'Promoter' ; and

(4) in case of an individual.

(i) any company in which 10% or more

of the share capital is held by the 'Promoter' or a relative of the 'Promoter' or a firm or Hindu undivided family in which the 'Promoter' or his relative is a partner or co-parcener or a combination thereof,

(ii) any company in which a company specified in (i) above, holds 10% or more of the share capital, or

(iii) any HUF or firm in which the aggregate share of the Promoter and his relatives is equal to or more than 10% of the total.

(i) "public financial institution" means a public financial institution as defined in Section 4A of the Companies Act, 1956.

(j) "public shareholding" means shareholding in the hands of person(s) other than the acquirer and persons acting in concert with him;

(k) "shares" means shares in the share capital of a company carrying voting rights and includes any security which would entitle the holder to receive shares with voting rights.

(l) "sick industrial company" shall have the same meaning assigned to it in clause (o) of sub-section (1) of Section 3 of the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985 (1 of 1986) or any statutory re-enactment thereof.

(m) "state level financial institution" means a state financial corporation established under Section 3 of the State Financial Institutions Act, 1951 and includes development corporation established as a company by a State Government with the object of development of industries or agricultural activities in the State;

(n) "stock exchange" means a stock exchange which has been granted recognition under Section 4 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956);

(o) "target company" means a listed company whose shares or voting rights or control is directly or indirectly acquired or is being acquired;

(2) All other expressions unless defined herein shall have the same meaning as have been assigned to them under the Act or the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, or the Companies Act, 1956, or any statutory modification or re-enactment thereto, as the case may be.

3. Applicability of the Regulation.—(1) Nothing contained in Regulations 10, 11 and 12 of these Regulations shall apply to :

(a) allotment in pursuance of an application made to a public issue,

Provided that if such an allotment is made pursuant to a firm allotment in the public issues, such allotment shall be exempt only if full disclosures are made in the prospectus about the identity of the acquirer who has agreed to acquire the shares, the purpose of acquisition, consequential changes in voting rights, shareholding pattern of the company and in the Board or Directors of the Company, if any, and whether such allotment would result in change in control over the company.

(b) allotment pursuant to an application made by the shareholder for rights issue,

(i) to the extent of his entitlement; and

(ii) upto the percentage specified in Regulation 11 :

Provided that the limit mentioned in sub-clause (ii) will not apply to the acquisition by any person presently in control of the company and who has in the rights letter of offer made disclosures that they intend to acquire additional shares beyond their entitlement, if the issue is undersubscribed :

Provided further that this exemption shall not be available in case the acquisition of securities results in the change of control of management.

(c) preferential allotment, made in pursuance of a resolution passed under Section 81(1A) of the Companies Act, 1956 (1 of 1956).

Provided that,

(i) Board Resolution in respect of the proposed preferential allotment is sent to all the stock exchanges on which the shares of the company are listed for being notified on the notice board;

(ii) full disclosures of the identity of the class of the proposed allottee(s) is made, and if any of the proposed allottee(s) is to be allotted such number of shares as would increase his holding to 5% or more of the post issued capital, then in such cases, the price at which the allotment is proposed, the identity of such person(s) the purpose of and reason for such allotment, consequential changes, if any, in the board of directors of the company and in voting rights, the shareholding pattern of the company, and whether such allotment would result in change in control over the company are all disclosed in the notice of the General Meeting called for the purpose of consideration of the preferential allotment;

(d) allotment to the underwriters pursuant to any underwriting agreement;

(e) *inter se* transfer of shares amongst :—

- (i) group companies, coming within the definition of group as defined in the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (25 of 1969);
- (ii) relatives within the meaning of Section 6 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956);
- (iii) (a) Indian promoters and foreign collaborators who are shareholders;
- (b) Promoters.

Provided that the transferor(s) as well as the transferee(s) in sub-clauses (a) and (b) have been holding individually or collectively not less than 5% shares in the target company for a period of at least three years prior to the proposed acquisition;

Explanation.—The benefit of availing of exemption from applicability of Regulations for increasing shareholding or *inter se* transfer of shareholding among group companies, relatives and promoters shall be subject to such group companies or relatives or promoters filing statements concerning group and individual shareholding as required under Regulations 6, 7 and 8.

(f) acquisition of shares in the ordinary course of business by,—

- (i) a registered stock-broker of a stock exchange on behalf of clients;
- (ii) a registered market maker of a stock exchange in respect of shares for which he is the market maker, during the course of market making;
- (iii) by Public Financial Institutions on their own account;
- (iv) by banks and public financial institutions as pledgees;
- (g) acquisition of shares by way of transmission on succession or inheritance;
- (h) acquisition of shares by government companies within the meaning of Section 617 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) and statutory corporations;
- (i) transfer of shares from state level financial institutions, including their subsidiaries, to co-promoter(s) of the company pursuant to an agreement between such financial institution and such co-promoter(s);

(j) pursuant to a scheme :—

- (i) framed under Section 18 of the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985;
- (ii) of arrangement or reconstruction including amalgamation or merger or demer-

ger under any law or regulation, Indian or foreign.

- (i) acquisition of shares in companies whose shares are not listed on any stock exchange;

Explanation : The exemption under clause (k) above shall not be applicable if by virtue of acquisition or change of control of any unlisted company, whether in India or abroad, the acquirer acquires shares or voting rights or control over a listed company.

- (1) such other cases as may be exempted from the applicability of Chapter III by the Board under Regulation 4.
- (2) Nothing contained in Chapter III of the Regulations shall apply to the acquisition of Global Depository Receipts or American Depository Receipts so long as they are not converted into shares carrying voting rights.
- (3) In respect of acquisitions under clauses (c), (e), (h) and (i) of sub-regulation (1), the stock exchanges where the shares of the company are listed shall, for information of the public, be notified of the details of the proposed transactions at least 4 working days in advance of the date of the proposed acquisition, in case of acquisition exceeding 2% of the voting share capital of the company.
- (4) In respect of acquisitions under clauses (a), (b), (c), (e) and (i) of sub-regulation (1), the acquirer shall, within 21 days of the date of acquisition, submit a report along-with supporting documents to the Board giving all details in respect of acquisitions which (taken together with shares or voting rights, if any, held by him or by persons acting in concert with him) would entitle such person to exercise 10% or more of the voting rights in a company.
- (5) The acquirer shall, along with the report referred to under sub-regulation (4), pay a fee of Rs. 10,000 to the Board, either by a bankers cheque or demand draft in favour of the Securities and Exchange Board of India, payable at Mumbai.

4. The Takeover Panel.—(1) The Board shall for the purposes of this Regulation constitute a Panel of majority of independent persons from within the categories mentioned in sub-section (5) of Section 4 of the Act.

(2) For seeking exemption under clause (1) of sub-regulation (1) of Regulation (3), the acquirer shall file an application with the Board, giving details of the proposed acquisition and the grounds on which the exemption has been sought.

(3) The acquirer shall, along with the application referred to under sub-regulation (2), pay a fee of Rs. 25,000 to the Board, either by a bankers cheque

or demand draft in favour of the Securities and Exchange Board of India, payable at Mumbai.

(4) The Board shall within 5 days of the receipt of an application under sub-regulation (2) forward the application to the Panel.

(5) The Panel shall within 15 days from the date of receipt of application make a recommendation on the application to the Board.

(6) The Board shall after affording reasonable opportunity to the concerned parties and after considering all the relevant facts including the recommendations, if any, pass a reasoned order on the application under sub-regulation (2) within 30 days thereof.

(7) The order of the Board under sub-regulation (6) shall be published by the Board.

5. Power of the Board.—In order to remove any difficulties in the interpretation or application of the provisions of these Regulations, the Board shall have the power to issue directions through guidance notes or circulars :

Provided that where any direction is issued by the Board in a specific case relating to interpretation or application of any provision of these Regulations, it shall be done only after affording a reasonable opportunity to the concerned parties and after recording reasons for direction.

CHAPTER II

DISCLOSURES OF SHAREHOLDING AND CONTROL IN A LISTED COMPANY

6. Transitional provision.—(1) Any person, who holds more than five per cent shares or voting rights in any company, shall within two months of notification of these Regulations disclose his aggregate shareholding in that company, to the company.

(2) Every company whose shares are held by the persons referred to in sub-regulation (1) shall, within three months from the date of notification of these Regulations, disclose to all the stock exchanges on which the shares of the company are listed, the aggregate number of shares held by each person.

(3) A promoter or any person having control over a company shall within two months of notification of these Regulations disclose the number and percentage of shares or voting rights held by him and by person(s) acting in concert with him in that company, to the company.

(4) Every company, whose shares are listed on a stock exchange, shall within three months of notification of these Regulations, disclose to all the stock exchanges on which the shares of the company are listed, the names and addresses of promoters and, or person(s) having control over the company, and number and percentage of shares or voting rights held by each such person.

7. Acquisition of 5% and more shares or voting rights of a company.—(1) Any acquirer, who acquires

shares or voting rights which (taken together with shares or voting rights, if any, held by him) would entitle him to more than five per cent shares or voting rights in a company, in any manner whatsoever, shall disclose the aggregate of his shareholding or voting rights in that company, to the company.

(2) The disclosures mentioned in sub-regulation (1) shall be made within four working days of,—

(a) the receipt of intimation of allotment of shares; or

(b) the acquisition of shares or voting rights, as the case may be.

(3) Every company, whose share are acquired in a manner referred to in sub-regulation (1), shall disclose to all the stock exchanges on which the shares of the said company are listed the aggregate number of shares held by each of such persons referred above within seven days of receipt of information under sub-regulation (1).

8. Continual disclosures.—(1) Every person, including a person mentioned in Regulation (6) who holds more than ten per cent shares or voting rights in any company, shall, within 21 days from the financial year ending March 31, make yearly disclosures to the company, in respect of his holdings as on 31st March.

(2) A promoter or every person having control over a company shall, within 21 days from the financial year ending March 31, as well as the record date of the company for the purposes of declaration of dividend, disclose the number and percentage of shares or voting rights held by him and by persons acting in concert with him, in that company to the company.

(3) Every company whose share are listed on a stock exchange, shall within 30 days from the financial year ending March 31, as well as the record date of the company for the purposes of declaration of dividend, make yearly disclosures to all the stock exchanges on which the shares of the company are listed, the changes, if any, in respect of the holdings of the persons referred to under sub-regulation (1) and also holdings of promoters or person(s) having control over the company as on 31st March.

(4) Every company whose shares are listed on a stock exchange shall maintain a register in the specified format to record the information received under sub-regulation (3) of Regulation (6), sub-regulation (1) of Regulation (7) and sub-regulation (2) of Regulation (8).

9. Power to call for information.—The stock exchanges and the company shall furnish to the Board information with regard to the disclosures made under Regulations 6, 7 and 8 as and when required by the Board.

CHAPTER III

SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES OR VOTING RIGHTS IN AND ACQUISITION OF CONTROL OVER A LISTED COMPANY

10. Acquisition of 10% or more of the shares or voting rights of any company.—No acquirer shall acquire shares or voting rights which (taken together with shares or voting rights, if any, held by him or by persons acting in concert with him), entitle such acquirer to exercise ten percent or more of the voting rights in a company, unless such acquirer makes a public announcement to acquire shares of such company in accordance with the Regulations.

11. (1) Consolidation of holdings.—(1) No acquirer who together with persons acting in concert with him has acquired, in accordance with the provisions of law, not less than 10% but not more than 51% of the shares or voting rights in a company, shall acquire, either by himself or through or with persons acting in concert with him, additional shares or voting rights entitling him to exercise more than 2% of the voting rights, in any period of 12 months, unless such acquirer makes a public announcement to acquire shares in accordance with the Regulations.

(2) No acquirer shall acquire shares or voting rights which (taken together with shares or voting rights, if any, held by him or by persons acting in concert with him), entitle such acquirer to exercise more than 51% of the voting rights in a company, unless such acquirer makes a public announcement to acquire share of such company in accordance with the Regulations.

Explanation.—For the purposes of Regulation 10 and Regulation 11, acquisition shall mean and include,—

- (a) direct acquisition in a listed company to which the Regulations apply;
- (b) indirect acquisition by virtue of acquisition of holding companies, whether listed or unlisted, whether in India or abroad.

12. Acquisition of control over a company.—Irrespective of whether or not there has been any acquisition of shares or voting rights in a company, no acquirer shall acquire control over the target company, unless such person makes a public announcement to acquire shares and acquires such shares in accordance with the Regulations.

Provided that nothing contained herein shall apply to any change in control which takes place in pursuance to a resolution passed by the shareholders in a general meeting.

Explanation.—(i) For the purposes of this Regulation where there are two or more persons in control over the target company, the cessor of any one such person from such control shall not be deemed to be a change in control of management nor shall any change in the nature and quantum of control amongst them constitute change in control of management.

Provided however that if the transfer of joint control to sole control is through sale at less than the

market value of the shares, a shareholders meeting of the target company shall be convened to determine mode of disposal of the shares of the outgoing shareholder, by a letter of offer or by block-transfer to the existing shareholders in control in accordance with the decision passed by a special resolution. Market value in such cases shall be determined in accordance with Regulation 20.

(ii) where any person or persons are given joint control, such control shall not be deemed to be a change in control so long as the control given is equal to or less than the control exercised by person(s) presently having control over the company.

13. Appointment of a Merchant Banker.—Before making any public announcement of offer referred to in Regulation 10 or Regulation 11 or Regulation 12, the acquirer shall appoint a merchant banker in Category I holding a certificate of registration granted by the Board, who is not associate of or group of the acquirer or the target company.

14. Timing of the Public Announcement of Offer.—(1) The public announcement referred to in Regulation 10 or Regulation 11 shall be made by the merchant banker not later than four working days of entering into an agreement for acquisition of shares or voting rights or deciding to acquire shares or voting rights exceeding the respective percentage specified therein.

(2) In case of an acquirer acquiring securities, including Global Depositories Receipts or American Depository Receipts which, when taken together with the voting rights, if any already held by him or persons acting in concert with him, would entitle him to voting rights, exceeding the percentage specified in Regulation 10 or Regulation 11, the public announcement referred to in sub-regulation (1) shall be made not later than four working days before he acquires voting rights on such securities upon conversion, or exercise of option, as the case may be.

(3) The public announcement referred to in Regulation 12 shall be made by the merchant banker not later than four working days after any such change or changes are decided to be made as would result in the acquisition of control over the target company by the acquirer.

15. Public Announcement of Offer.—(1) The public announcement to be made under Regulations 10 or 11 or 12 shall be made in all editions of one English national daily with wide circulation, one Hindi national daily with wide circulation and a regional language daily with wide circulation at the place where the registered office of the target company is situated and at the place of the stock exchange where the shares of the target company are most frequently traded.

(2) A copy of the public announcement to be made under Regulations 10, 11 or 12 shall be submitted to the Board through the merchant banker at least two working days before its issuance.

(3) Simultaneous with the submission of the public announcement to the Board, the public announcement shall also be sent to all the stock exchanges on which

the shares of the company are listed for being notified on the notice board, and to the target company at its registered office for being placed before the board of directors of the Company

(4) The offer under these Regulations shall be deemed to have been made on the date on which the public announcement has appeared in any of the newspapers referred to in sub-regulation (1).

16. Contents of the Public Announcement of Offer.—The public announcement referred to in Regulations 10 or 11 or 12 shall contain the following particulars, namely :—

- (i) the paid up share capital of the target company, the number of fully paid up and partly paid up shares;
- (ii) the total number and percentage of shares proposed to be acquired from the public, subject to a minimum as specified in sub-regulation (1) of Regulation 21;
- (iii) the minimum offer price for each fully paid up or partly paid up share;
- (iv) mode of payment of consideration;
- (v) the identity of the acquirer(s) and in case the acquirer is a company or companies, the identity of the promoters and, or the persons having control over such company(ies) and the group, if any, to which the company(ies) belong;
- (vi) the existing holding, if any, of the acquirer in the shares of the target company, including holdings of persons acting in concert with him;
- (vii) salient features of the agreement, if any, such as the date, the name of the seller, the price at which the shares are being acquired, the manner of payment of the consideration and the number and percentage of shares in respect of which the acquirer has entered into the agreement to acquire the shares or the consideration, monetary or otherwise, for the acquisition of control over the target company, as the case may be;
- (viii) the highest and the average price paid by the acquirer or persons acting in concert with him for acquisition, if any, of shares of the target company made by him during the twelve month period prior to the date of public announcement;
- (ix) object and purpose of the acquisition of the shares and future plans, if any, of the acquirer for the target company, including disclosures whether the acquirer proposes to dispose of or otherwise encumber any assets of the target company in the succeeding two years, except in the ordinary course of business of the target company.

Provided that where the future plans are set out, the public announcement shall also set out how the acquirers propose to implement such future plans.

- (x) the 'specified date' as mentioned in Regulation 19.
- (xi) the date by which individual letters of offer would be posted to each of the shareholders;
- (xii) the date of opening and closure of the offer and the manner in which and the date by which the acceptance or rejection of the offer would be communicated to the shareholders;
- (xiii) the date by which the payment of consideration would be made for the shares in respect of which the offer has been accepted;
- (xiv) disclosure to the effect that firm arrangement for financial resources required to implement the offer is already in place, including details regarding the sources of the funds whether domestic i.e. from banks, financial institutions, or otherwise or foreign i.e. from Non-Resident Indians or otherwise.
- (xv) provision for acceptance of the offer by person(s) who own the shares but are not the registered holders of such shares.
- (xvi) statutory approvals, if any, required to be obtained for the purpose of acquiring the shares under the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), The Foreign Exchange Regulation Act, 1973, (46 of 1973) and/or any other applicable laws;
- (xvii) approvals of banks or financial institutions required, if any;
- (xviii) whether the offer is subject to a minimum level of acceptance from the shareholders and
- (xix) such other information as is essential for the shareholders to make an informed decision in regard to the offer.

17. Brochures, advertising material etc.—The public announcement of the offer or any other advertisement, circular, brochure, publicity material or letter of offer issued in relation to the acquisition of shares shall not contain any misleading information.

18. Submission of Letter of offer to the Board.—
(1) Within fourteen days from the date of public announcement made under Regulation 10, 11 or 12 as the case may be, the acquirer shall, through its merchant banker, file with the Board, the draft of the letter of offer, containing disclosures as specified by the Board.

(2) The letter of offer shall be despatched to the shareholders not earlier than 21 days from its submission to the Board under sub-regulation (1).

Provided that if, within 21 days from the date of submission of the letter of offer, the Board specifies changes, if any, in the letter of offer, (without being under any obligation to do so) the merchant banker and the acquirer shall carry out such changes before the letter of offer is despatched to the shareholders.

(3) The acquirer shall, alongwith the draft letter of offer referred to in sub-regulation (1), pay a fee of Rs. 50,000 to the Board, either by a banker's cheque or demand draft in favour of the Securities and Exchange Board of India, payable at Mumbai.

19. Specified date.—The public announcement shall specify a date, which shall be the 'specified date' for the purpose of determining the names of the shareholders to whom the letter of offer should be sent.

Provided that such specified date shall not be later than the thirtieth day from the date of the public announcement.

20. Minimum offer price.—(1) The offer to acquire the shares under Regulations 10, 11 or 12 shall be made at a minimum offer price which shall be payable—

- (a) in cash; or
- (b) by exchange and, or transfer of shares of acquirer company, if the person seeking to acquire the shares is a listed body corporate; or
- (c) by exchange and/or transfer of secured instruments with a minimum of 'A' grade rating from a credit rating agency;
- (d) a combination of clauses (a), (b) or (c).

Provided that where payment has been made in cash to any class of shareholders for acquiring their shares under any agreement or pursuant to any acquisition in the open market or in any other manner during the preceding 12 months from the date of public announcement, the offer document shall provide that the shareholders have the option to accept payment either in cash or by exchange of shares or other secured instruments referred to above.

(2) For the purposes of sub-regulation (1), the minimum offer price shall be the highest of—

- (a) the negotiated price under the agreement referred to in sub-regulation (1) of Regulation 14.
- (b) highest price paid by the acquirer or persons acting in concert with him for any acquisitions, including by way of allotment in a public or rights issue, if any, during the 26 week period prior to the date of public announcement;
- (c) the price paid by the acquirer under a preferential allotment made to him or to persons acting in concert with him at any time during the twelve months period upto the date of closure of the offer;
- (d) the average of the weekly high and low of the closing prices of the shares of the target company as quoted on the stock exchange where the shares of the company are most frequently traded during the 26 weeks preceding the date of public announcement.

(3) Where the shares of the target company are infrequently traded, the offer price shall be determined by the issuer and the merchant banker taking into account the following factors :

- (a) the negotiated price under the agreement referred to in sub-regulation (1) of Regulation 14;
- (b) highest price paid by the acquirer or persons acting in concert with him for acquisitions including by way of allotment in a public or rights issue, if any, during the twenty six week period prior to the date of public announcement;
- (c) the price paid by the acquirer under a preferential allotment made to him or to persons acting in concert with him, at any time during the twelve month period upto the date of closure of the offer, and
- (d) other parameters including return on networth, book value of the shares of the target company, earning per share, price earning multiple vis-a-vis the industry average.

Explanation :—(i) For the purpose of this clause, shares will be deemed to be infrequently traded if on the stock exchange, the annualised trading turnover in that share during the preceding 6 calendar months prior to the month in which the public announcement is made is less than two per cent (by number of shares) of the listed shares. For this purpose, the weighted average number of shares listed during the said six months period may be taken.

(ii) In case of shares which have been listed within six months preceding the public announcement, the trading turnover may be annualised with reference to the actual number of days for which the share has been listed.

(4) Notwithstanding the provisions of sub-regulations (1) (2) and (3) above, where the acquirer has acquired shares in the open market or through negotiation or otherwise, after the date of public announcement at a price higher than the minimum offer price stated in the letter of offer, then the highest price paid for such acquisition shall be payable for all acceptances received under the offer.

(5) In case where shares or secured instruments of the acquirer company are offered in lieu of cash payment, the value of such shares or secured instruments shall be determined in the same manner as mentioned in sub-regulations (2) and (3) above to the extent applicable, as duly certified by an independent Category I Merchant Banker (other than the managers to the offer) or an independent Chartered Accountant of 10 years standing.

(6) The letter of offer shall contain justification on the basis on which the price has been determined.

Explanation :—(1) The highest price under clause (b) or the average price under clause (d) of

sub-regulation (2) may be adjusted for quotations, if any, or cum-rights or cum-bonus basis during the said period.

(2) Where the public announcement of offer is pursuant to acquisition by way of firm allotment in a public issue or preferential allotment, the average price under clause (d) of sub-regulation 2 shall be calculated with reference to the 26 week period preceding the date of the board resolution which authorised the firm, preferential allotment.

(3) Where the shareholders have been provided with an option to accept payment either in cash or by way of exchange of security then subject to the provisions of Regulation 20, the pricing for the cash offer could be different from that of a share exchange offer or offer for exchange with secured instruments, provided that the disclosures in the offer documents contains suitable justification for such differential pricing.

(4) Where the offer is subject to a minimum level of acceptances, the acquirer may subject to the provision of Regulation 20, indicate a lower price for the minimum acceptance of 20%, should the offer not receive full acceptance.

21. Minimum number of Shares to be acquired.—

(1) The public offer shall be made to the shareholders of the target company to acquire from them an aggregate minimum of 20% of the voting capital of the company.

Provided that where the open offer is made in pursuance to sub-regulation (2) of Regulation 11, the public offer shall be for such percentage of the voting capital of the company as may be decided by the acquirer.

(2) Where the offer is conditional upon a minimum level of acceptances from the shareholders as provided for in clause (xviii) of Regulation 16, the provisions of sub-regulation (1) of this regulation shall not be applicable, if the acquirer has deposited in the escrow account in cash a sum of 50% of the consideration payable under the public offer.

(3) If the public offer results in the public shareholding being reduced to 10% or less of the voting capital of the company, or if the public offer is in respect of a company which has public shareholding of less than 10% of the voting capital of the company, the acquirer shall either,—

(a) within a period of 3 months from the date of closure of the public offer, make an offer to buy out the outstanding shares remaining with the shareholders at the same offer price, which may result in delisting of the target company; or

(b) undertake to disinvest through an offer for sale or by a fresh issue of capital to the public, which shall open within a period of 6 months from the date of closure of the public offer, such number of shares so as to satisfy the listing requirements.

(4) The letter of offer shall state clearly the option available to the acquirer under sub-regulation (3).

(5) For the purpose of computing the percentage referred to sub-regulation (1), (2) and (3) the voting rights as at the expiration of 30 days after the closure of the public offer shall be reckoned.

(6) Where the number of shares offered for sale by the shareholders are more than the shares agreed to be acquired by the person making the offer, such person shall, accept the offers received from the shareholders on a proportional basis, in consultation with the merchant banker, taking care to ensure that the basis of acceptance is decided in a fair and equitable manner and does not result in non-marketable lots.

Provided that acquisition of shares from a shareholder shall not be less than the minimum marketable lot or the entire holding if it is less than the marketable lot.

22. General Obligations of the acquirer.—(1) The public announcement of offer to acquire the shares of the target company shall be made only when the acquirer is able to implement the offer.

(2) Within 14 days of the public announcement of the offer, the acquirer shall send a copy of the draft letter of offer to the target company at its registered office address, for being placed before the board of directors and to all the stock exchanges where the shares of the company are listed.

(3) The acquirer shall ensure that the letter of offer is sent to all the shareholders (including non-resident Indians) of the target company, whose names appear on the register of members of the company as on the specified date mentioned in the public announcement, so as to reach them within 45 days from the date of public announcement.

Provided that where the public announcement is made pursuant to an agreement to acquire shares or control over the target company, the letter of offer shall be sent to shareholders other than the parties to the agreement.

Explanation.—(i) A copy of the letter of offer shall also be sent to the Custodians of Global Depository Receipts or American Depository Receipts to enable such persons to participate in the open offer, if they are entitled to do so.

(ii) A copy of the letter of offer shall also be sent to warrant holders or convertible debenture holders, where the period of exercise of option or conversion falls within the offer period.

(4) The date of opening of the offer shall be not later than the sixtieth day from the date of public announcement.

(5) The offer to acquire shares from the shareholders shall remain open for a period of 30 days.

(6) In case the acquirer is a company, the public announcement of offer, brochure, circular, letter of

offer or any other advertisement or publicity material issued to shareholders in connection with the offer must state that the directors accept the responsibility for the information contained in such documents.

Provided that if any of the directors desires to exempt himself from responsibility for the information in such document, such director shall issue a statement to that effect, together with reasons thereof for such statement.

(7) During the offer period, the acquirer or persons acting in concert with him shall not be entitled to be appointed on the board of directors of the target company.

(8) Where an offer is made conditional upon minimum level of acceptances, the acquirer or any person acting in concert with him—

- (i) shall, irrespective of whether or not the offer received response to the minimum level of acceptances, acquire shares from the public to the extent of the minimum percentage specified in sub-regulation (1) of Regulation 21.

Provided that the provisions of this clause shall not be applicable in case the acquirer has deposited in the escrow account, in cash, 50% of the consideration payable under the public offer.

- (ii) shall not acquire, during the offer period, any shares in the target company, except by way of fresh issue of shares of the target company, as provided for under Regulation 3;
- (iii) shall be liable for penalty of forfeiture of entire escrow amount, for the non-fulfilment of obligations under the Regulations;

(9) If any of the persons representing or having interest in the acquirer is already a director on the board of the target company or is an "insider" within the meaning of Securities and Exchange Board of India (Insider Trading) Regulations, 1992, he shall recuse himself and not participate in any matter(s) concerning or 'relating' to the offer including any preparatory steps leading to the offer.

(10) On or before the date of issue of public announcement of offer, the acquirer shall create an escrow account as provided under Regulation 28.

(11) The acquirer shall ensure that firm financial arrangements has been made for fulfilling the obligations under the public offer and suitable disclosures in this regard shall be made in the public announcement of offer.

(12) The acquirer shall, within a period of 30 days from the date of the closure of the offer, complete all procedures relating to the offer including payment of consideration to the shareholders who have accepted the offer and for the purpose open a special account as provided under Regulation 29. Provided that where the acquirer is unable to make the payment to the shareholders who have

accepted the offer before the said period of 30 days due to non-receipt of requisite statutory approvals, the Board may, if satisfied that non-receipt of requisite statutory approvals was not due to any wilful default or neglect of the acquirer or failure of the acquirer to diligently pursue the applications for such approvals, grant extension of time for the purpose, subject to the acquirer agreeing to pay interest to the shareholders for delay beyond 30 days, as may be specified by the Board from time to time.

(13) Where the acquirer fails to obtain the requisite statutory approvals in time on account of wilful default or neglect or inaction or nonaction on his part, the amount lying in the escrow account shall be liable to be forfeited and dealt with in the manner provided in clause (c) of sub-regulation 12 of Regulation 28, apart from the acquirer being liable for penalty as provided in the Regulations.

(14) In the event of withdrawal of offer in terms of the Regulations, the acquirer shall not make any offer for acquisition of shares of the target company for a period of six months from the date of public announcement of withdrawal of offer.

(15) In the event of non-fulfilment of obligations under Chapter III or Chapter IV of the Regulations the acquirer shall not make any offer for acquisition of shares of any listed company for a period of twelve months from the date of closure of offer.

(16) If the acquirer, in pursuance to an agreement, acquires shares which along with his existing holding, if any, increases his shareholding beyond 10%, then such an agreement for sale of shares shall contain a clause to the effect that in case of non-compliance of any provisions of this regulation, the agreement for such sale shall not be acted upon by the seller or the acquirer.

(17) Where the acquirer or persons acting in concert with him has acquired any shares after the date of public announcement he, shall disclose the number, percentage, price and the mode of acquisition of such shares to the stock exchanges on which the shares of the target company are listed and to the merchant banker, within 24 hours of such acquisition.

(18) Where the acquirer has not either, in the public announcement, and, or in the letter of offer, stated his intention to dispose of or otherwise encumber any assets of the target company except in the ordinary course of business of the target company, the acquirer, where he has acquired control over the target company, shall be debarred from disposing of or otherwise encumbering the assets of the target company for a period of 2 years from the date of closure of the public offer.

23. General Obligations of the board of directors of the target company.—(1) Unless the approval of the general body of shareholders is obtained after the date of the public announcement of offer, the board of directors of the target company shall not, during the offer period,—

- (a) sell, transfer, encumber or otherwise dispose of or enter into an agreement for sale, transfer, encumbrance or for disposal of assets otherwise, not being sale or disposal of assets in the ordinary course of business, of the company or its subsidiaries; or
- (b) issue any authorised but unissued securities carrying voting rights during the offer period; or
- (c) enter into any material contracts.

Explanation.—Restriction on issue of securities under clause (b) of sub-regulation (1) shall not affect the right of the target company to issue and allot shares carrying voting rights upon conversion of debentures already issued or upon exercise of option against warrants, as per pre-determined terms of conversion/exercise of option.

(2) The target company shall furnish to the acquirer, within 7 days of the request of the acquirer or within 7 days from the specified date whichever is later, a list of shareholders or warrant holders or convertible debenture holders as are eligible for participation under Explanation (ii) to sub-regulation (1) of Regulation 22 containing names, addresses, shareholding and folio number, and of those persons whose applications for registration of transfer of shares are pending with the company.

(3) Once the public announcement has been made, the board of directors of the target company shall not,—

- (a) appoint as additional director or fill in any casual vacancy on the board of directors, by any person(s) representing or having interest in the acquirer, till the date of certification by the merchant banker as provided under sub-regulation (6) below.

Provided that upon closure of the offer and the full amount of consideration payable to the shareholders being deposited in the special account, changes as would give the acquirer representation on the Board or control over the company can be made by the target company.

- (b) allow any person or persons representing or having interest in the acquirer, if he is already a director on the board of the target company before the date of the public announcement, to participate in any matter relating to the offer, including any preparatory steps leading thereto.

(4) The board of directors of the target company may, if they so desire, send their unbiased comments and recommendations on the offer(s) to the shareholders, keeping in mind the fiduciary responsibility of the directors to the shareholders and for the purpose seek the opinion of an independent merchant banker or a Committee of Independent Directors;

Provided that for any misstatement or for concealment of material information, the directors shall be liable for action in terms of these Regulations and the Act.

(5) The board of directors of the target company shall facilitate the acquirer in verification of securities tendered for acceptances.

(6) Upon fulfilment of all obligations by the acquirers under the Regulations as certified by the merchant banker, the board of directors of the target company shall transfer the securities acquired by the acquirer, whether under the agreement or from open market purchases, in the name of the acquirer and or allow such changes in the board of directors as would give the acquirer representation on the board or control over the company.

(7) The obligations provided for in sub-regulation (16) of regulation 22 shall be complied with by the company in the circumstances specified therein.

24. General obligations of the merchant banker.—

(1) Before the public announcement of offer is made, the merchant banker shall ensure that—

- (a) the acquirer is able to implement the offer;
- (b) the provision relating to escrow account referred to in Regulation 28 has been made;
- (c) firm arrangements for funds and money for payment through verifiable means to fulfil the obligations under the offer are in place;
- (d) the public announcement of offer is made in terms of the Regulations.

(2) The merchant banker shall furnish to the Board a due diligence certificate which shall accompany the draft letter of offer.

(3) The merchant banker shall ensure that the draft public announcement and the letter of offer is filed with the Board, target company and also sent to all the stock exchanges on which the shares of the target company are listed in accordance with the Regulations.

(4) The merchant banker shall ensure that the contents of the public announcement of offer as well as the letter of offer are true, fair and adequate and based on reliable sources, quoting the source wherever necessary.

(5) The merchant banker shall ensure compliance of the Regulations and any other laws or rules as may be applicable in this regard.

(6) Upon fulfilment of all obligations by the acquirers under the Regulations, the merchant banker shall cause the bank with whom the escrow amount has been deposited to release the balance amount to the acquirers.

(7) The merchant banker shall send a final report to the Board within 45 days from the date of closure of the offer.

25. Competitive bid.—(1) Any person, other than the acquirer who has made the first public announcement, who is desirous of making any offer, shall, within 21 days of the public announcement of the first offer, make a public announcement of his offer for acquisition of the shares of the same target company.

Explanation : An offer made under sub-regulation (1) shall be deemed to be a competitive bid.

(2) No public announcement for an offer or competitive bid shall be made after 21 days from the date of public announcement of the first offer.

(3) Any competitive offer by an acquirer shall be for such number of shares which, when taken together with shares held by him alongwith persons acting in concert with him, shall be atleast equal to the number of shares for which the first public announcement has been made.

(4) Upon the public announcement of a competitive bid or bids, the acquirer(s) who had made the public announcement(s) of the earlier offer(s), shall have the option to make an announcement:—

- (a) revising the offer; or
- (b) withdrawing the offer, with the prior approval of the Board;

Provided that if no such announcement is made within fourteen days of the announcement of the competitive bid(s), the earlier offer(s) on the original terms shall continue to be valid and binding on the acquirer(s) who had made the offer(s) except that the date of closing of the offer shall stand extended to the date of closure of the public offer under the last subsisting competitive bid.

(5) The provisions of these Regulations shall mutatis-mutandis apply to the competitive bid(s) made under sub-regulation (1).

(6) The acquirers who have made the public announcement of offer(s) including the public announcement of competitive bid(s) but have not withdrawn the offer in terms of sub-regulation (4) shall have the option to make upward revisions in his offer(s), in respect to the price and the number of shares to be acquired, at any time upto seven working days prior to the date of closure of the offer :

Provided that the acquirer shall not have the option to change any other terms and conditions of their offer.

Provided further that any such upward revision shall be made only upon the acquirer,—

- (a) making a public announcement in respect of such changes or amendments in all the newspapers in which the original public announcement was made ;
- (b) simultaneously with the issue of public announcement referred in clause (a), informing the Board, all the stock exchanges

on which the shares of the company are listed, and the target company at its registered office;

- (c) increasing the value of the escrow account as provided under sub-regulation (9) of Regulation 28.

(7) Where there is a competitive bid, the date of closure of the original bid as also the date of closure of all the subsequent competitive bids shall be the date of closure of public offer under the last subsisting competitive bid and the public offers under all the subsisting bids shall close on the same date.

26. Upward Revision of Offer.—Irrespective of whether or not there is a competitive bid, the acquirer who has made the public announcement of offer may make upward revisions in his offer in respect to the price and the number of shares to be acquired, at anytime upto seven working days prior to the date of the closure of the offer :

Provided that any such upward revision of offer shall be made only upon the acquirer—

- (a) making a public announcement in respect of such changes or amendments in all the newspapers in which the original public announcement was made;
- (b) simultaneously with the issue of such public announcement, informing the Board, all the stock exchanges on which the shares of the company are listed, and the target company at its registered office.
- (c) increasing the value of the escrow account as provided under sub-regulation (9) of Regulation 28.

27. Withdrawal of Offer.—(1) No public offer, once made, shall be withdrawn except under the following circumstances:—

- (a) the withdrawal is consequent upon any competitive bid;
- (b) the statutory approval(s) required have been refused;
- (c) the sole acquirer, being a natural person, has died;
- (d) such circumstances as in the opinion of the Board merits withdrawal.

(2) In the event of withdrawal of the offer under any of the circumstances specified under sub-regulation (1), the acquirer or the merchant banker shall:

- (a) make a public announcement in the same newspapers in which the public announcement of offer was published, indicating reasons for withdrawal of the offer.
- (b) simultaneously with the issue of such public announcement, inform—(i) the Board; (ii) all the stock exchanges on which the

shares of the company are listed; and (iii) the target company at its registered office.

28. Provision of Escrow.—(1) The acquirer shall as and by way of security for performance of his obligations under the Regulations, deposit in an escrow account such sum as specified in sub-regulation (2).

(2) The escrow amount shall be calculated in the following manner,—

(a) For consideration payable under the public offer,—

upto and including Rs. 100 crores—25% ;

exceeding Rs. 100 crores—25% ;

upto Rs. 100 crores and 10% thereafter.

(b) For offers which are subject to a minimum level of acceptance, and the acquirer does not want to acquire a minimum of 20% , than 50% of the consideration payable under the public offer in cash shall be deposited in the escrow amount.

(3) The total consideration payable under the public offer shall be calculated assuming full acceptances and at the highest price if the offer is subject to differential pricing, irrespective of whether the consideration for the offer is payable in cash or otherwise.

(4) The escrow account referred in sub-regulation (1) shall consist of,—

(a) cash deposited with a scheduled commercial bank or;

(b) bank guarantee in favour of the merchant banker; or

(c) deposit of acceptable securities with appropriate margin, with the merchant banker; or

(d) cash, deposited with a scheduled commercial bank in case of clause (b) of sub-regulation (2) of this Regulation.

(5) Where the escrow account consists of deposit with a scheduled commercial bank, the acquirer shall, while opening the account, empower the merchant banker appointed for the offer to instruct the bank to issue a banker's cheque or demand draft for the amount lying to the credit of the escrow account, as provided in the Regulations.

(6) Where the escrow account consists of bank guarantee, such bank guarantee shall be in favour of the merchant banker and shall be valid atleast for a period commencing from the date of public announcement until 30 days after the closure of the offer.

(7) The acquirer shall, in case the escrow account consists of securities empower the merchant banker to realise the value of such escrow account by sale or otherwise provided that if there is any deficit on realisation of the value of the securities, the merchant banker shall be liable to make good any such deficit.

(8) In case the escrow account consists of bank guarantee or approved securities, these shall not be returned by the merchant banker till after completion of all obligations under the Regulations.

(9) In case there is any upward revision of offer, consequent upon a competitive bid or otherwise, the value of the escrow account shall be increased to equal at least 10% of the consideration payable upon such revision.

(10) Where the escrow account consist of bank guarantee or deposit of approved securities, the acquirer shall also deposit with the bank a sum of at least 1% of the total consideration payable, as and by way of security for fulfilment of the obligations under the Regulations by the acquirers.

(11) The Board shall in case of non-fulfilment of obligations under the Regulations by the acquirer forfeit the escrow account either in full or in part.

(12) The escrow account deposited with the bank in cash shall be released only in the following manner,—

(a) the entire amount to the acquirer upon withdrawal of offer in terms of Regulation 27 upon certification by the merchant banker;

(b) for transfer to the special account opened in terms of sub-regulation (1) of Regulation 29 :

Provided the amount so transferred shall not exceed 90% of the cash deposit made under clause (a) of sub-regulation (2) of this regulation.

(c) to the acquirer, the balance of 10% of the cash deposit made under clause (a) of Sub-regulation (2) of this Regulation or the cash deposit made under Sub-regulation (8) of this Regulation, on completion of all obligations under the Regulations, and upon certification by the merchant banker;

(d) the entire amount to the acquirer upon completion of all obligations under the Regulations, upon certification by the merchant banker, where the offer is for exchange of shares or other secured instruments;

(e) the entire amount to the merchant banker, in the event of forfeiture for non-fulfilment of any of the obligations under the Regulations, for distribution among the target company, the regional stock exchange and to the shareholders who had accepted the offer in the following manner, after deduction of expenses, if any, of the merchant banker and the registrars to the offer—

(i) one third of the amount to the target company;

(ii) one-third of the amount to the regional stock exchange for credit of the investor protection fund or any other similar fund for investor education, research.

grievance redressal and similar such purposes as may be specified by the Board from time to time;

- (iii) residual one-third to be distributed prorata among the shareholders who have accepted the offer.

(13) In the event of non-fulfilment of obligations by the acquirer, the merchant banker shall ensure realisation of escrow amount by way of foreclosure of deposit invocation of bank guarantee or sale of securities and credit proceeds thereof to the regional stock exchange of the target company, for the credit of the Investor Protection Fund or any other similar fund.

29. Payment of consideration.—(1) For the amount of consideration payable in cash, the acquirer shall, within a period of 21 days from the date of closure of the offer, open a special account with a Bankers to an Issue registered with the Board and deposit therein, such sum as would, together with 90% of the amount lying in the escrow account, if any, make up the entire sum due and payable to the shareholders as consideration for acceptances received and accepted in terms of these Regulations and for this purpose, transfer the funds from the escrow account.

(2) The unclaimed balance lying to the credit of the account referred in sub-regulation (1) at the end of 3 years from the date of deposit thereof shall be transferred to the investor protection fund of the regional stock exchange of the target company.

(3) In respect of consideration payable by way of exchange of securities, the acquirer shall ensure that the securities are actually issued and despatched to the shareholders.

CHAPTER IV BAIL OUT TAKEOVERS

30. Bail out takeovers.—(1) The provisions of this Chapter shall apply to a substantial acquisition of shares in a financially weak company not being a sick industrial company, in pursuance to a scheme of rehabilitation approved by a public financial institution or a scheduled bank; (hereinafter referred to as lead institution).

(2) The lead institution shall be responsible for ensuring compliance with the provisions of this Chapter.

(3) The lead institution shall appraise the financial weak company taking into account the financial viability, and assess the requirement of funds for revival and draw up the rehabilitation package on the principle of protection of interests of minority shareholders, good management, effective revival and transparency.

(4) The rehabilitation scheme shall also specifically provide the details of any change in management.

(5) The scheme may provide for acquisition of shares in the financially weak company in any of the following manner:

- (a) outright purchase of shares, or

(b) exchange of shares, or

(c) a combination of both.

Provided that the scheme as far as possible may ensure that after the proposed acquisition the erstwhile promoters do not own any shares in case such acquisition is made by the new promoters pursuant to such scheme.

Explanation : For the purpose of this chapter, the expression "financially weak company" means a company, which has at the end of the previous financial year accumulated losses, which has resulted in erosion of more than 50% but less than 100% of its net-worth as at the beginning of the previous financial year, that is to say, of the sum total of the paid-up capital and free reserves.

31. Manner of acquisition of shares.—(1) Before giving effect to any scheme of rehabilitation the lead institution shall invite offers for acquisition of shares from atleast three parties.

(2) After receipt of the offers under sub-regulation (1), the lead institution shall select one of the parties having regard to the managerial competence, adequacy of financial resources and technical capability of the person acquiring shares to rehabilitate the financially weak company.

(3) The lead institution shall provide necessary information to any person intending to make an offer to acquire shares about the financially weak company and particularly in relation to its present management technology, range of products manufactured, shareholding pattern, financial holding and performance and assets and liabilities of such company for a period covering five years from the date of the offer as also the minimum financial and other commitments expected of from the person acquiring shares for such rehabilitation.

32. Manner of evaluation of bids.—(1) The lead institution shall evaluate the bids received with respect to the purchase price or exchange of shares, track record, financial resources, reputation of the management of the person acquiring shares and ensure fairness and transparency in the process.

(2) After making evaluation as provided in sub-regulation (1), the offers received shall be listed in order of preference and after consultation with the persons in the affairs of the management of the financially weak company accept one of the bids.

33. Person acquiring shares to make an offer.—The person acquiring shares who has been identified by the lead institution under sub-regulation 2 of Regulation 32, shall on receipt of a communication in this behalf from the lead institution make a formal offer to acquire shares from the promoters or persons in charge of the affairs of the management of the financially weak company, financial institutions and also other shareholders of the company at a price determined by mutual negotiation between the person acquiring the shares and the lead institution.

Explanation : Nothing in this regulation shall prohibit the lead institution offering the shareholdings held by it in the financially weak company as part of the scheme of rehabilitation.

34. Person acquiring shares to make public announcement.—(1) The person acquiring shares from the promoters or the persons in charge of the management of the affairs of the financially weak company or the financial institution shall make a public announcement of his intention for acquisition of shares from the other shareholders of the company.

(2) Such public announcement shall contain relevant detail about the offer including the information about the identity and background of the person acquiring shares, number and percentage of shares proposed to be acquired, offer price, the specified date, the date of opening of the offer and the period for which the offer shall be kept open and such other particulars as may be required by the board.

(3) The letter of offer shall be forwarded to each of the shareholders other than the promoters or the persons in charge of management of the financially weak company and the financial institutions.

(4) If the offer referred to in sub-regulation (1) results in the public shareholding being reduced to 10% or less of the voting capital of the company, the acquirer shall either—

(a) within a period of three months from the date of closure of the public offer, make an offer to buy out the outstanding shares remaining with the shareholders at the same offer price, which may have the effect of delisting the target company; OR

(b) or undertake to disinvest through an offer for sale or by a fresh issue of capital to the public which shall open within a period of 6 months from the date of closure of public offer, such number of shares so as to satisfy the listing requirements.

(5) The letter of offer shall state clearly the option available to the acquirer under sub-regulation (4).

(6) For the purposes of computing the percentage referred to in the sub-regulation (4), the voting rights as at the expiration of thirty days after the closure of the public offer shall be reckoned.

(7) While accepting the offer from the shareholders other than the promoters or persons in charge of the financially weak company or the financial institutions, the person acquiring shares shall offer to acquire from the individual shareholder his entire holdings if such holding is upto hundred shares of the face value of rupees ten each or ten shares of the face value of rupees hundred each.

35. Competitive Bid.—No person shall make a competitive bid for acquisition of shares of the financially weak company once the lead institution has evaluated the bid and accepted the bid of the acquirer who has made the public announcement of

offer for acquisition of shares from the shareholders other than the promoters or the persons in charge of the management of the financially weak company.

36. Exemption from the operations of Chapter III.—(1) Every offer which has been made in pursuance of Regulation 30 shall be accompanied with an application to the Board for exempting such acquisitions from the provisions of Chapter III of these Regulations.

(2) For considering such request the Board may call for such information from the company as also from the lead institution, in relation to the manner of vetting the offers evaluation of such offers and similar other matters.

(3) Notwithstanding grant of exemption by the Board, the lead institution or the acquirer as far as may be possible, shall adhere to the time limits specified for various activities for public offer specified in Chapter III

37. Acquisition of shares by a state level public financial institution.—Where proposals for acquisition of shares in respect of a financially weak company is made by a state level public financial institution, the provisions of these Regulations in so far as they relate to scheme of rehabilitation prepared by a public financial institution, shall apply except that in such a case the Industrial Development Bank of India, a corporation established under the Industrial Development Bank of India Act, 1964 shall be the agency for ensuring the compliance of these Regulations for acquisition of shares in the financially weak company.

CHAPTER V

INVESTIGATION AND ACTION BY THE BOARD

38. Board's right to investigate :—The Board may appoint one or more persons as investigating officer to undertake investigation for any of the following purposes, namely :—

(a) to investigate into the complaints received from the investors, the intermediaries or any other person on any matter having a bearing on the allegations of substantial acquisition of shares and takeovers ;

(b) to investigate suo-moto upon its own knowledge or information, in the interest of securities market or investors interests, for any breach of the Regulations ;

(c) to ascertain whether the provisions of the Act and the Regulations are being complied for any breach of the Regulations;

39. Notice before investigation :—(1) Before ordering an investigation under Regulation 38, the Board shall give not less than 10 days notice to the acquirer, the seller, the target company, the merchant banker, as the case may be,

(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), where the Board is satisfied that in the interest of the investors no such notice should be given, it may, by an order in writing direct that such investigation be taken up without such notice.

(3) During the course of an investigation, the acquirer, the seller, the target company, the merchant banker, against whom the investigation is being carried out shall be bound to discharge his obligation as provided in Regulation 40.

40. Obligations on investigation by the Board :—

(1) It shall be the duty of the acquirer, the seller, the target company, the merchant banker whose affairs are being investigated and of every director, officer and employee thereof, to produce to the investigating officer such books, securities, accounts, records and other documents in its custody or control and furnish him with such statements and information relating to his activities as the investigating officer may require, within such reasonable period as the investigating officer may specify.

(2) The acquirer, the seller, the target company, the merchant banker and the persons being investigated shall allow the investigating officer to have reasonable access to the premises occupied by him or by any other person on his behalf and also extend reasonable facility for examining any books, records, documents and computer data in the possession of the acquirer, the seller, the target company, the merchant banker or such other person and also provide copies of documents or other materials which, in the opinion of the investigating officer are relevant for the purposes of the investigation.

(3) The investigating officer, in the course of investigation, shall be entitled to examine or to record the statements of any director, officer or employee of the acquirer, the seller, the target company, the merchant banker.

(4) It shall be the duty of every director, officer or employee of the acquirer, the seller, the target company, the merchant banker to give to the investigating officer all assistance in connection with the investigation, which the investigating officer may reasonably require.

41. Submission of Report to the Board :—The investigating officer shall, as soon as possible, on completion of the investigation, submit a report to the Board :—

Provided that if directed to do so by the Board, he may submit interim reports.

42. Communication of findings :—(1) The Board shall, after consideration of the investigation report referred to in Regulation 41, communicate the findings of the investigating officer to the acquirer, the seller, the target company, the merchant banker, as the case may be, and give him an opportunity of being heard.

(2) On receipt of the reply if any, from the acquirer, the seller, the target company, the merchant banker, as the case may be, the Board may call upon him to take such measures as the Board may deem fit in the interest of the securities market and for due compliance with the provisions of the Act and the Regulations.

43. Appointment of Auditor :—Notwithstanding anything contained in this Regulation, the Board may appoint a qualified auditor to investigate into the books of account or the affairs of the person concerned :—

Provided that the auditor so appointed shall have the same powers of the investigating authority as stated in Regulation 38 and the obligations of the person concerned in Regulation 40 shall be applicable to the investigation under this Regulation.

44. Directions by the Board :—The Board may, in the interests of the securities market, without prejudice to its right to initiate action including criminal prosecution under section 24 of the Act give such directions as it deems fit including :—

- (a) directing the person concerned not to further deal in securities ;
- (b) prohibiting the person concerned from disposing of any of the securities acquired in violation of these Regulations ;
- (c) directing the person concerned to sell the shares acquired in violation of the provisions of these Regulations ;
- (d) taking action against the person concerned.

45. Penalties for non-compliance :—(1) Any person violating any provisions of the Regulations shall be liable for action in terms of the Regulations and the Act.

(2) If the acquirer or any person acting in concert with him, fails to carry out the obligations under the Regulations, the entire or part of the sum in the escrow amount shall be liable to be forfeited and the acquirer or such a person shall also be liable for action in terms of the Regulations and the Act.

(3) The board of directors of the target company failing to carry out the obligations under the Regulations shall be liable for action in terms of the Regulations and Act.

(4) The Board may, for failure to carry out the requirements of the Regulations by an intermediary, initiate action for suspension or cancellation of registration of an intermediary holding a certificate of registration under section 12 of the Act.

Provided that no such certificate of registration shall be suspended or cancelled unless the procedure specified in the Regulations applicable to such intermediary is complied with.

(5) For any mis-statement to the shareholders or for concealment of material information required to be disclosed to the shareholders, the acquirers or the directors where the acquirer is a body corporate, the directors of the target company, the merchant banker to the public offer and the merchant banker engaged by the target company for independent advice would be liable for action in terms of the Regulations and the Act.

(6) The penalties referred to in sub-regulation (1) to (5) may include :—

- (a) criminal prosecution under section 24 of the Act ;
- (b) monetary penalties under section 15 H of the Act ;
- (c) directions under the provisions of Section 11-B of the Act.

46. Appeal to the Central Government :—Any person being aggrieved by an order of the Board under these Regulations may prefer an appeal to the Central Government.

47. Repeal and Saving :—(1) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 1993 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal :—

- (a) Anything done or any action taken or purporting to have been done or taken including approval of letter of offer exemption granted, fees collected any adjudication, enquiry or investigation commenced or showcause notice issued under the said regulations shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these regulations ;
- (b) Any application made to the Board under the said regulations and pending before it shall be deemed to have been made under the corresponding provisions of these regulations.
- (c) Any appeals preferred to the Central Government under the said regulations and pending before it shall be deemed to have been preferred under the corresponding provisions of these regulations.

[F. No. SEBI/LE/XVII|1|541|97]

D. R. MEHTA, Chairman.
Securities & Exchange Board of India

